सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-41 अंक 6 | 22 मार्च से 5 अप्रैल 2026 | मुख्य संपादक: कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

महान कार्ल मार्क्स जिन्दाबाद

5 मई 1818—14 मार्च 1883

"जो असम्भव है, वे उसके लिए लालायित हैं। यानी ये लोग पूंजीवादी जीवन की अवस्थाओं को, बिना इन अवस्थाओं के अनिवार्य परिणामों के, चाहते हैं। इनमें से कोई भी यह नहीं समझता कि उत्पादन का पूंजीवादी रूप सामंतवादी रूप की तरह ही ऐतिहासिक और अनित्य है। इस भूल का कारण यह है कि उनके लिए पूंजीवादी मानव ही प्रत्येक समाज का एकमात्र सम्भव आधार है, वे ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते, जिसमें मानव पूंजीवादी मानव नहीं रह जायेगा।" –कार्ल मार्क्स (आन्नेनकोव के नाम पत्र 28 दिसम्बर 1846)

महान कार्ल मार्क्स को दी क्रांतिकारी श्रद्धांजलि

महान कार्ल मार्क्स की 143वीं बरसी पर उन्हें याद करते हुए 14 मार्च को शिवपुर सेंटर में एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभास घोष ने महान कार्ल मार्क्स की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहां मौजूद केन्द्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी।

अमेरिका लगातार दे रहा है ईरान को बर्बाद कर देने की धमकी

पश्चिम एशिया के आसमान में साम्राज्यवादी गिद्ध मंडरा रहे हैं। इस बार उनके निशाने पर ईरान है। आज की अत्याधुनिक तकनीक से लैस मिसाइलें अपने निशाने पर सटीक हमला करने में तनिक भी गलती नहीं करतीं। जबकि 28 फरवरी को अमेरिका-इजरायल की साम्राज्यवादी जोड़ी द्वारा हमला शुरू करने के बाद ही ईरान में 6 से 12 साल की बच्चियों का एक स्कूल मिसाइल हमले से ध्वस्त हो गया। देखते ही देखते फूल जैसी 200 बच्चियां काल के गाल में समा गईं। इस लेख के तैयार किये जाने तक प्राप्त खबरों के मुताबिक अमेरिका के बर्बर हमले में ईरान के लगभग डेढ़ हजार लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 30 फीसदी बच्चे हैं। मकान के अंदर मिसाइल हमला करके ईरान के सर्वोच्च धार्मिक शासक अयातुल्लाह अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया गया है। उधर ईरान ने पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर जवाबी हमले किये हैं। कुल मिलाकर कहा जाये, तो बारूद की गंध, बमों से जमींदोज हुए मकानों, अस्पतालों और स्कूलों के ध्वंसावशेषों से उड़ रही धूल-गर्द, घायलों की चीख-पुकार और मृतकों के परिजनों की रुलाई से अब पश्चिम एशिया की हवा बोझिल हो चुकी है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। ईरान सहित पश्चिम एशिया का यह क्षेत्र कच्चे तेल व गैस जैसे महत्वपूर्ण ईंधन की आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत होने और ईरान द्वारा तेलों से भरे जहाजों के आवागमन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हार्मूज जलडमरूमध्य को बंद कर देने से पूरी दुनिया के देश संकट में पड़ गये हैं। भारत सरकार ने भी उपभोक्ताओं की रसोई गैस की आपूर्ति में कटौती की है और युद्ध के मौके का फायदा उठाकर साथ ही साथ इसके दाम भी बढ़ा दिये है।

ईरान पर यह हमला क्यों है? जंगखोर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया है कि अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान के हमले की संभावना थी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा है कि ईरान के हमले को रोकने के लिए ही पहले से उस पर हमला करने का यह कार्यक्रम है। लेकिन यह पूरी तरह से उजागर हो गया है कि इन दोनों की बातें सरासर झूठी हैं। अमेरिकी प्रतिरक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने 1 मार्च को

(शेष पृष्ठ 2 पर)

राजनैतिक वित्तपोषण के जरिये चुनाव पर कॉर्पोरेट घरानों का नियंत्रण

भारत के पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, एसआईआर) के नाम से एक कवायद की गई है ताकि कई असली भारतीय नागरिकों और असली मतदाताओं के नाम इससे बाहर किये जा सकें, जिनकी पहचान सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ संभावित मतदाता के रूप में की गई है। लेकिन यह धनबल-बाहुबल-संचार माध्यमों व प्रशासनिक बल का इस्तेमाल करके चुनाव नतीजों में हेरफेर करने के मौजूदा तरीके से अलग है। इसलिए भारत के 'सबसे बड़ा लोकतंत्र' होने के बड़े-बड़े दावों के बावजूद यह बड़े साफ-तौर पर जाहिर हो गया है कि चुनाव एक मजाक बनकर रह गया है।

बुर्जुआ चुनावी राजनीति और पैसे का खेल

शासक-एकाधिकारी तय करते हैं, महान लेनिन के शब्दों में, ''केवल संसदीय-संवैधानिक राजतंत्रों में ही नहीं, बल्कि अधिक से अधिक जनवादी जनतंत्रों में भी कुछ वर्षों पर एक बार यह फैसला करना ही पूंजीवादी संसदीय व्यवस्था का सच्चा सार है कि शासक वर्ग का कौन सदस्य संसद में जाकर जनता का दमन और उत्पीड़न करेगा।" (राज्य और क्रांति)। इसे कार्यान्वित करने के लिए पैसे पर वे सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं। जमा कर रखे गये धन के भंडार का एक छोटा-सा हिस्सा अपनी पसंद की पार्टी या पार्टियों के कोष में दे दिया जाता है ताकि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार उनकी पसंद की और उनकी ताबेदार हो। इसलिए एकाधिकारी पूंजीपति घराने और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी पसंदीदा पार्टी या गठबंधन में "बढ़ावा देती" हैं ताकि वे गद्दी पर बैठने के बाद एवज में उन्हें नाजायज सहूलियत मुहैया करायें। इसी तरह जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले, काला धन रखने वाले और शासक पूंजीपति वर्ग की मेहरबानी से फलने-फूलने वाले जमीन-जायदाद की खरीद-बेच आदि रीयल एस्टेट के बड़े कारोबारी भी उन पार्टियों को पैसा देते हैं, जिनके बारे में वे जानते हैं कि वे धनकुबेरों और बड़े उद्योगपतियों के द्वारा की जा रही लूट और उत्पीड़न के प्रबंधक हैं। इसलिए ऐसी पार्टियों की सरकारें उनकी गैरकानूनी गतिविधियों

(शेष पृष्ठ 7 पर)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले 230 सीटों पर लड़ रही एसयूसीआई (सी)

कोलकाता में एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) राज्य कार्यालय में केन्द्रीय और राज्य नेतृत्व की मौजूदगी में 16 मार्च को एक पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पार्टी के राज्य सचिव सह पोलित ब्यूरो सदस्य कॉमरेड चंडीदास भट्टाचार्य ने कहा, "आगामी विधानसभा चुनाव में हम अकेले 230 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार के चुनाव की विशेषता यह है कि चुनाव आयोग ने 60 लाख से अधिक 'विचाराधीन' मतदाताओं का फैसला किये बिना ही चुनाव की घोषणा कर दी है। हमारी पार्टी के कई प्रस्तावित उम्मीदवार भी इस विचाराधीन सूची में होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अगर अगले तीन सप्ताह के भीतर इसका निपटारा नहीं हुआ, तो लाखों लोग मताधिकार से वंचित हो जायेंगे। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और एक निश्चित समय के भीतर विचाराधीन मतदाताओं की जांच पूरी करने की मांग करते हैं। इसके अलावा, जिन लोगों के नाम 'डिलीट' कर दिये गये हैं, अगर वे फॉर्म 6 भरकर जमा करते हैं, तो आयोग को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाये।"

कॉमरेड भट्टाचार्य ने आगे कहा, "इस चुनाव में दो घोर भ्रष्टाचारी और जनविरोधी सत्ताधारी पार्टियां–राज्य की तृणमूल कांग्रेस और केन्द्र की भाजपा–एक-दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। धनबल, बाहुबल और संगठित प्रचार तंत्र के जरिये नफरत, द्वेष और हिंसा का बाजार गर्म है। रोटी-रोजी के संकट, महंगाई, शिक्षा और इलाज की समस्याओं से तंगो-तबाह अमनपसंद मेहनतकश आम अवाम राजनीतिक खेमाबंदी, ध्रुवीकरण, झड़प और हंगामे की दहशत में जी रहा है।"

भाजपा का ताबेदार चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर इस राज्य में पिछले कई महीनों से दरअसल जनता के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। वह घुसपैठ के नाम पर जनता से नागरिकता का सबूत मांग रहा है, जो आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बार-बार निर्देशों में बदलाव और 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) के नाम पर अनगिनत वैध नागरिकों –खासकर अल्पसंख्यकों, महिलाओं, मतुआ समुदाय, आदिवासियों और गरीबों–को नोटिस थमाया गया है। हैरत की बात यह है कि इनमें न्यायाधीश, बीएलओ, पूर्व सांसद और सचिव भी शामिल हैं। भाजपा इन सभी को रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर इनकी नागरिकता छीनने की धमकी दे रही है और सांप्रदायिक नफरत व हिंसा का माहौल बना रही है। दूसरी ओर एसआईआर की दहशत और मानसिक तनाव के कारण बीएलओ सहित लगभग डेढ़ सौ लोगों की मौत और आत्महत्या जैसी घटनाएं घट चुकी हैं। भले ही भाजपा खुद को हिन्दुओं की रक्षक बताती है, लेकिन उसने मतुआ समुदाय के हजारों लोगों के मताधिकार को बचाने की कोई व्यवस्था नहीं की। एक तरफ पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल में भी प्रशासन, पार्टी का गुलाम बन चुका है, तो दूसरी तरफ केन्द्र की सत्ताधारी भाजपा के निर्देश पर चुनाव आयोग तमाम नियमों को ताक पर रखकर तरह-तरह के निर्देश

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अमेरिका ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

बताया कि ईरान की ओर से हमले की कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। दरअसल हमला शुरू होने से पहले ओमान की मध्यस्थता में ईरान और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण बातचीत चल रही थी। 27 फरवरी को ओमान के विदेश मंत्री ने बताया था कि परमाणु बम बनाने के साजो-सामान मौजूद न रखने और भविष्य में परमाणु बम न बनाने के वायदे सहित ईरान एक समझौते के करीब पहुंच चुका है। जबकि इस घोषणा के महज कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने अचानक ईरान पर मिसाइल हमारा शुरू कर दिया। यानी अब तक ठीक जिस तरह से अफगानिस्तान, इराक, लीबिया सहित एक के बाद एक कई देशों पर हमला करने से पहले अमेरिकी साम्राज्यवाद ने कभी जन संहारक हथियारों की मौजूदगी, तो कभी लोकतंत्र के खतरे में पड़ने जैसे तरह-तरह के झूठे बहाने बनाता रहा है, इस बार ईरान पर हमले के मामले में भी इसका कोई अपवाद नहीं हुआ। इस प्रसंग में जिक्र किया जा सकता है कि 2015 में अमेरिका, चीन, रूस सहित और कई पश्चिमी देशों के साथ ईरान का जो परमाणु समझौता हुआ था, 2018 में अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप सरकार खुद ही उस समझौते से अलग हो गयी थी। 2025 में जब नये सिरे से परमाणु शक्ति को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई, तभी यह झूठा आरोप लगाकर कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, 22 जून को पहले इजरायल और उसके बाद अमेरिका ने उस पर हमला किया। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस हैं।

कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ईरान में खामेनेई के धार्मिक कट्टरपंथी शासन से ईरानी जनता को बचाने के लिए और जनवादी अधिकारों की बहाली के लिए ही अमेरिका ने यह हमला किया है। उन्हें याद रखना चाहिए कि खामेनेई के खिलाफ उस देश के लोगों के जनवादी अधिकार छीनने के जो अनगिनत आरोप हैं, उसे लेकर ईरान की जनता काफी दिनों से संघर्षरत है। उसने कभी भी इस संघर्ष में अमेरिका या इजरायल से मदद नहीं मांगी। इसके अलावा, जिस इजरायल ने गजा में बर्बरतापूर्ण हमले चलाकर कई लाख निहत्थे फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया, जिस अमेरिका ने अचानक हमले कर एक संप्रभु देश वेनेजुएला के राष्ट्रपति का सपत्नीक अपहरण कर लिया, क्या उनके मुंह से दूसरे देशों के लोकतंत्र की रक्षा की बात शोभा देती है? दुनिया के लोगों ने बार-बार गौर किया है कि लोकतंत्र खतरे में है, हुकूमत बदलनी चाहिए जैसी बातों की आड़ में जब भी अमेरिकी साम्राज्यवाद ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया आदि मुल्कों पर हमले किये, तो इनमें से हर देश मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और हुक्मरानों की कुर्सी पर या तो अमेरिकी साम्राज्यवाद की कठपुतली सरकार या फिर धार्मिक कट्टरपंथी ताकतें काबिज हुईं। इसलिए लोकतंत्र का झंडाबरदार अमेरिका और इजरायल खुद ही दूसरे देशों के लोकतंत्र और उनकी संप्रभुता के सबसे बड़े हत्यारे हैं, यह बात आज जगजाहिर हो चुकी है।

दरअसल अमेरिकी साम्राज्यवाद काफी दिन पहले से ही ईरान पर हमले की योजना बना रहा था। उसका मकसद तेल और गैस से समृद्ध पश्चिम एशिया में अपना एकछत्र दबदबा कायम करना है। इस काम में उस क्षेत्र में इजरायल उसका एक प्रमुख सहयोगी रहा है। सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन और कतर जैसे कई पश्चिम एशियाई देशों से अमेरिकी साम्राज्यवाद का हित सधता है। लेकिन अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा समर्थित इजरायल की फिलिस्तीन में दखलंदाजी के खिलाफ जो संघर्षशील सशस्त्र समूह लड़ रहे हैं, उनका सक्रिय रूप से समर्थन करने वाले देशों में ईरान एक प्रमुख देश है। ईरान में एक तरफ कच्चे तेल का विशाल भंडार है, तो दूसरी तरफ फारस की खाड़ी, हार्मूज जलडमरूमध्य और क्षेत्रीय ताकतों के शक्ति संतुलन में ईरान की स्थिति ऐसी है कि अगर इस देश पर लगाम नहीं लगायी गयी, तो अमेरिकी साम्राज्यवाद के लिए पश्चिम एशिया में अपना समग्र वर्चस्व काम करना कठिन है। इसलिए साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपनाकर पहली बार परमाणु हथियार तैयार करने का झूठा आरोप लगाकर और इस बार बातचीत की मेज पर बैठकर सहमति पर पहुंचने का नाटक करते-करते ही ईरान में अमेरिका और इजरायल निरंतर हमले कर रहे हैं। अगर ईरान को घुटना टेकने पर मजबूर कर दिया गया, तो जिस तरह तेल का विशाल भंडार उसके कब्जे में आ जायेगा, उसी तरह पश्चिम एशिया में अमेरिकी साम्राज्यवादी वर्चस्व का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा।

कुछ-कुछ हलकों में यह माना जा रहा है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के पीछे एक और वजह भी है। तेल के टैंकरों के आवागमन के लिए जो हार्मूज जलडमरूमध्य अत्यंत उपयोगी है, वह ईरान के कब्जे में है। अगर ईरान पर कब्जा कर लिया जाये, तो इस जलडमरूमध्य पर अमेरिका का नियंत्रण कायम हो जायेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे अमेरिका को चीन में तेल की आपूर्ति बाधित करने का मौका मिल जायेगा। उसे इस मौके की जरूरत है, क्योंकि दिन पर दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था में वर्चस्व कायम करने के मामले में चीन अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

ईरान में कट्टरपंथी धार्मिक लबादे की आड़ में शोषणकारी पूंजीवादी शासन कायम है। स्वाभाविक रूप दुनिया के तमाम पूंजीवादी देशों की तरह ही उसके खिलाफ भी वहां के लोगों में काफी रोष-आक्रोश है। पिछले कई सालों से ईरान के लोगों को बार-बार विभिन्न मांगों पर सड़कों पर उतरते देखा गया है। इस जनविक्षोभ ने बार-बार विशाल रूप धारण किया है और अन्य पूंजीवादी देशों की तरह ही ईरान के शासको ने भी इन आंदोलनो का बर्बरतापूर्वक दमन किया है। लेकिन ईरान में अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायल की दखलअंदाजी के पक्ष में यह कोई तर्क नहीं हो सकता। दरअसल, अपने साम्राज्यवादी हित साधने के लिए ही ये दोनों देश ईरान पर बेशर्मी से हमला चला रहे हैं। इन हमलों से अमेरिकी 'युद्ध उद्योग' में जान आयेगी। बाजार संकट यानी मंदी में फंसी हुई अमेरिकी अर्थव्यवस्था राहत की सांस लेगी। इस मरणासन्न पूंजीवाद के युग में अमेरिकी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है उसका युद्ध उद्योग। उसके रक्षा मद में हर साल काफी धन आवंटित किया जाता है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन, नॉरथ्रॉप ग्रुम्मन और बोइंग जैसी कंपनियां दुनिया में हथियार बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां में शीर्ष पर हैं। अगर विभिन्न देशों से युद्ध न हो, तो उनके द्वारा बड़ी मात्रा में बनाये हथियारों की खपत कैसे होगी? अमेरिकी संसद में बड़ी हथियार निर्माता कंपनियों और तेल कंपनियों के मालिक बैठे हुए हैं।

इसलिए बिना किसी उकसावे के ईरान जैसे प्राचीन विरासत से समृद्ध इतिहास में मशहूर एक देश पर हमला कर सभ्यता के विभिन्न साक्ष्यों और प्रतीकों सहित अनगिनत निर्दोष लोगों को मौत घाट उतारने का प्रस्ताव पास कराने में ट्रंप साहब को वहां कोई दिक्कत नहीं हुई। यही पूंजीवाद-साम्राज्यवाद का असली रूप है। समाज-सभ्यता को तबाही की हद तक पहुंचाने वाली इस भयंकर साम्राज्यवादी बर्बरता के सामने खड़े होकर आज समाजवादी खेमे की गैरमौजूदगी खास तौर पर खल रही है। अगर दुनिया में समाजवादी खेमा रहता, तो साम्राज्यवाद अपना यह वीभत्स रूप दिखाने की जुर्रत नहीं कर पाता।

लेकिन बर्बरता ही अंतिम बात नहीं है। इसलिए ईरान पर अमेरिका-इजरायल के बर्बर साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है। विभिन्न देशों में अमन पसंद और जनवादी सोच वाले हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। खुद अमेरिका में ही विभिन्न शहरों में रोजाना नागरिकों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस ट्रंप ने 13 महीने के अपने कार्यकाल में कम से कम सात देशों पर हमला किया है, उनके अपने बेटे को ईरान के खिलाफ युद्ध में भेजने की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं।

भारत के लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं। साम्राज्यवाद का विरोध भारत की लंबे दिनों की परंपरा रही है। जबकि ईरान पर अमेरिका-इजरायल साम्राज्यवादी हमले की निंदा कर एक बयान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की बर्बरतापूर्ण हत्या पर भी दुख प्रकट करने में भाजपा सरकार को 5 दिन लग गये। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ईरान पर हमला करने की योजना बन रही थी, ठीक उसी समय प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर जाकर उस देश की सरकार के बगल में खड़े रहने का संदेश दे आये। समझा जा सकता है कि दिन पर दिन अमेरिका-इजरायल साम्राज्यवादी धुरी की ओर भाजपा की केन्द्र सरकार ज्यादा से ज्यादा झुकती जा रही है। भारत के युद्ध-विरोधी और जनवादपसंद लोग इसके खिलाफ मुखर हुए हैं। अमेरिका-इजरायल फौरन ईरान पर हमले बंद कर ईरान की स्वतंत्रता और संप्रभुता बरकरार रखें, इस मांग पर पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन को ताकतवर बनाना ही आज समय की मांग है।

पश्चिम बंगाल ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

जारी कर रहा है। यहां तक कि उसने मुख्य सचिव और गृह सचिव को रातों-रात हटा देने जैसा अभूतपूर्व कदम उठाया है।

विभिन्न राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री जिस तरह से धार्मिक अल्पसंख्यकों को परेशान करने, प्रताड़ित करने और यहां तक कि उनकी हत्या के लिए उग्र धर्मांध पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। इसके साथ धर्म का कोई लेना-देना नहीं है। सर्वविदित है कि धर्मांधता और कट्टरता के खिलाफ इसी बंगाल में राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, रवींद्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम ने धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद का परचम बुलंद किया था, लेकिन काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज उसी बंगाल में 21वीं सदी में धर्म ग्रंथों के पाठ को भी सत्ताधारी पार्टियां चुनावी संघर्ष में इस्तेमाल कर रही हैं। इसमें लेशमात्र भी धार्मिक मूल्य या भक्ति भाव नहीं है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस हिन्दू वोट बैंक की रक्षा के लिए एक तरफ जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर और महाकाल मंदिर बनवा रही है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम वोटों के लिए भाजपा की उग्र सांप्रदायिकता से डरी हुई मुस्लिम जनता के सामने 'मसीहा' की भूमिका में आने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने डर दिखाया है कि अगर एक 'समुदाय' एकजुट हो गया, तो क्या हो सकता है, जबकि प्रधानमंत्री ने इसके जवाब में 'चुन-चुनकर हिसाब लेने' की धमकी दी है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों पर बैठे ये दोनों लोग इस तरह आतंक का माहौल तैयार कर रहे हैं, जो अत्यंत निंदनीय है।

इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पूंजीपतियों के बेलगाम शोषण की वजह से देश के लोगों की क्रय शक्ति लगभग खत्म होने को है। लाखों कल-कारखाने बंद हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। पूरे देश के साथ-साथ इस राज्य में भी बेरोजगारी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। स्कीम वर्करों की लम्बे समय से चली आ रही जायज मांगें केन्द्र या राज्य, कोई भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। चाय बागान के मजदूर अपने तमाम अधिकारों से वंचित हैं। चाय बागान के बेबस मजदूरों के परिवारों की लड़कियां बड़ी तादाद में मानव तस्करी का शिकार हो रही हैं। युवा मामूली मजदूरी पर नौकरी पाने के लिए, यहां तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर विभिन्न राज्यों में पलायन कर रहे हैं। प्रवासी मजदूरों, खासकर भाजपा शासित राज्यों से, को केवल बांग्ला बोलने की वजह से अंतहीन अपमान और यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ ही दिन पहले, कोलकाता में एक बंद गोदाम में मोमो फैक्ट्री के लगभग चालीस मजदूर जिन्दा जलकर मर गये। सरकार स्थायी रोजगार प्रदान करने के बजाय बेरोजगार युवाओं को मामूली भत्तों पर निर्भर बना रही है और सरकारी धन से वोट खरीदने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही है।

कांग्रेस लम्बे समय से इस देश के पूंजीपति वर्ग की सेवा करती रही है। वर्तमान में इसी की निरंतरता में देशी-विदेशी पूंजीपतियों के हित में केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने घोर मजदूर-विरोधी चार श्रम संहिताएं लागू कर न्यूनतम मजदूरी व सुरक्षा सहित मजदूरों के अधिकारों को छीनने का काम किया है। स्थायी रोजगार की अवधारणा को ही खत्म किया जा रहा है। भारतीय एकाधिकार पूंजीपतियों के हित साधने के लिए केन्द्र की भाजपा सरकार ने किसानों, मछुआरों, पशुपालकों सहित आम लोगों की रोजी-रोटी के हितों की बलि चढ़ाते हुए अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता किया है। इस समझौते के जरिये पूंजीपतियों के हितों के लिए जनता के हितों और सम्मान की भावना को अमेरिकी साम्राज्यवाद के हाथों कुर्बान कर दिया गया है। इससे खाद्यान्न, दूध और दुग्ध उत्पादों के बाजार पर अमेरिकी बहुराष्ट्रीय पूंजी का कब्जा हो जायेगा। नतीजतन, इस देश के किसानों को बड़ी आपदा का सामना करना पड़ेगा। दूसरी ओर, अमेरिकी और इजरायली जंगखोरों द्वारा ईरान पर बिना किसी उकसावे के एकतरफा हमला करने की वजह से तेल समेत आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका है। इसी अवसर का लाभ उठाते हुए रसोई गैस की कीमत में एकाएक 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गयी है। महिलाओं व बच्चियों की हत्या समेत नरसंहार के मुख्य सूत्रधार अमेरिकी और इजरायली हुक्मरानों के साथ खुलेआम बदनुमा तालमेल साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की परंपरा पर चलने वाली भारत की जनवादपसंद जनता को दुखी कर रहा है।

केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर एक ओर तो शिक्षा का पूर्ण निजीकरण शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के मूल तत्व, वैज्ञानिक तर्कसंगतता को

(शेष पृष्ठ 4 पर)

सही लोकतान्त्रिक-धर्मनिरपेक्ष व जनवादी मूल्यों को स्थापित करना ही भेदभाव व उत्पीड़न को मिटाने की होगी असली गारंटी

धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, विकलांगता इत्यादि के आधार पर देशभर में बढ़ रहे भेदभाव के संदर्भ में 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026 आया। इस यूजीसी रेगुलेशन के आते ही एक पक्ष ने इसकी कुछ कमी-खामियों के बावजूद इसे स्वागतयोग्य बताया, वहीं दूसरे पक्ष ने इसे सामान्य वर्ग के छात्र हितों के खिलाफ बताया और इसको वापस लेने की मांग की। इसके पक्ष और विपक्ष में देशभर में हुए प्रदर्शनों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। फिर भी शिक्षण संस्थानों सहित पूरे देश में इस रेगुलेशन पर बहस छिड़ी हुई है। कई संस्थानों में दोनों पक्षों के बीच झड़पें भी हुई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हुए एक कार्यक्रम में इतिहासकार एस. इरफान हबीब पर घृणित हमला भी हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक जातिगत आधार पर छात्र आपस में बंट गए हैं। ऐसे में इस पूरे प्रकरण की संक्षिप्त, लेकिन आलोचनात्मक पड़ताल जरूरी है।

पृष्ठभूमि

हमारे देश के खास सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश में सदियों से जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न एक सच्चाई है। न केवल जातिगत, बल्कि आज पूरा देश धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग व संप्रदाय आधारित भेदभाव की आग में झुलस रहा है। इसी का प्रतिबिम्बन हम उच्च शिक्षण संस्थानों में देख रहे हैं। वैसे तो इन भेदभावों को खत्म करने के लिए कानून बनाये जाते रहे हैं, लेकिन विशेषकर उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने की बात कहकर 2012 में यूजीसी रेगुलेशन लाया गया था। इस रेगुलेशन के बावजूद शिक्षण संस्थानों में जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती गयीं। 2016 में रोहित वेमुला और 2019 में पायल थडवी की संस्थागत हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। जातिगत उत्पीड़न को खत्म करने के लिए नए और सख्त कानून की मांग उठने लगी। हाल ही में यूजीसी द्वारा संसदीय समिति व सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई रिपोर्ट कहती है कि देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों में पिछले पांच वर्षों में 118.4% की वृद्धि हुई है। इस संबंध में दर्ज की गई घटनाओं की संख्या 2019-20 में 173 से बढ़कर 2023-24 में 378 हो गई है। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव व उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यूजीसी रेगुलेशन 2026 आता है।

इस रेगुलेशन में 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा में ओ.बी.सी. (अन्य पिछड़ा वर्ग) को भी जोड़ा गया है, जो 2012 के रेगुलेशन में नहीं था। 2026 के रेगुलेशन को वैधानिक दर्जा दिया गया है, जबकि 2012 का रेगुलेशन महज एक एडवाइजरी की तरह था। इसमें विभिन्न तरह के लोगों को मिलाकर दस सदस्यीय 'समता समिति' (Equity Committee) और 'समता समूह' (Equity Squad) बनाने का प्रावधान है। समता समूह पूरे संस्थान में घूम-घूम कर किसी भी प्रकार के भेदभाव की घटना होने पर समान अवसर केन्द्र (Equal Opportunity Centre) के को-ऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करेगा। इसमें 'समता दूत' (Equity Ambassador) की भी बात की गई है, जो संस्थान की हर इकाई में होगा और जिसका काम यह सुनिश्चित करना होगा कि इस रेगुलेशन के तहत 'समान अवसर केन्द्र' द्वारा जारी निर्देशों का सही-सही पालन हो। किसी भी शिकायत के दर्ज होने पर 24 घंटे के अंदर समता समिति को बैठक बुलाकर घटना का संज्ञान लेना होगा और 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख को सौंपनी होगी। इसके बाद संस्थान के प्रमुख को 7 दिन के अंदर उचित कार्रवाई शुरू करनी होगी। रेगुलेशन को सही से पालन न करने पर संस्थान की मान्यता तक रद्द करने का प्रावधान है। इसलिए यह रेगुलेशन 2012 के रेगुलेशन से ज्यादा सख्त है।

विरोध का कारण

इस रेगुलेशन के आते ही एक पक्ष द्वारा विरोध शुरू कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। इस विरोध का कारण उन्होंने यह बताया कि रेगुलेशन भेदभाव को बढ़ाने वाला है; इसमें दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। रेगुलेशन कुछ खास वर्गों के ही अधिकारों की बात करता है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों को इस रेगुलेशन में प्रदत्त अधिकारों से वंचित रखा गया है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पर अंतरिम रोक लगा दी है और इसकी पुनः जांच करने को कहा है।

हालांकि कानूनी नजरिये से इस रेगुलेशन में अगर सुधार की जरूरत है, तो वह होना चाहिए। लेकिन किसी भी नजरिये से क्या आज के वक्त में भेदभाव व जातिगत उत्पीड़न से इनकार किया जा सकता है, जिसके भुक्तभोगी सीधे तौर पर शोषित-पीड़ित और तथाकथित निम्न वर्ग के लोग हो रहे हैं? ध्यान रखने की बात है कि यूजीसी रेगुलेशन जातिगत भेदभावों सहित तमाम तरह के भेदभावों पर रोक लगाने का दावा करता है। ऐसे में यह निहायत जरूरी है कि कानूनी तौर पर जो भी सुधार हों, वे सुधार इन जातिगत उत्पीड़नों व अन्य तमाम भेदभावों पर रोक लगाने में रेगुलेशन को और भी सख्त बनाये।

हमारा नजरिया और छात्रों व तमाम शैक्षणिक समुदाय से अपील

आज स्पष्ट तौर पर देश में दो पक्षों के बीच लड़ाई चल रही है। जहां एक पक्ष इस नियम को लागू करवाने के लिए लड़ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इसे रुकवाने के लिए। इसे रोकने वाले पक्ष की आवाज निश्चित तौर पर प्रतिक्रियावादियों की है या भ्रमित लोगों की। लेकिन एक गंभीर सवाल देश के प्रगतिशील लोगों के सामने भी चुनौती के तौर पर है कि क्या पहले से कई नियमों, अनुशासन समितियों और जांच समितियों के बाद एक नया नियम आने से भेदभाव और उत्पीड़न पर रोक लगेगी? आज चाहे जातिगत हो या अन्य किसी भी प्रकार के भेदभाव व उत्पीड़न हों, क्या सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश की ऐसी गंभीर चुनौतियों को महज कानूनों के जरिये हल कर पाना सम्भव है? शायद ही कोई इसका उत्तर 'हां' में दे।

इस संदर्भ में आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी, एआईडीएसओ के मार्गदर्शक व महान मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष ने कहा था, ''हम सभी जानते हैं कि भारतीय पूंजीवाद का विकास एक खास परिस्थिति में हुआ है। जिस राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग ने इस देश में राष्ट्रीय आजादी आन्दोलन का नेतृत्व किया, वह शुरू से ही साम्राज्यवाद और सामंतवाद के साथ समझौता करते हुए सत्ता पर काबिज हुआ। इसकी वजह से वह समाज के जनवादीकरण के लिए आवश्यक सामाजिक-सांस्कृतिक क्रांति के कार्यक्रमों को पूरा करने और अलग-अलग भाषाएं बोलने वाले, विभिन्न उपराष्ट्रीयताओं वाले तथा अलग-अलग धर्म मानने वाले विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों का एकीकरण करते हुए उन्हें एक राष्ट्रीयता में तब्दील करने में विफल रहा। इस प्रकार वह सही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना नहीं कर सका। इस संबंध में एक और बात हमेशा याद रखने की जरूरत है। वह है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जनता सिर्फ आर्थिक शोषण का ही शिकार नहीं होती है, बल्कि उसमें उपराष्ट्रीय उत्पीड़न भी होता है। यही वजह है कि जिन पूंजीवादी देशों में एक से अधिक उपराष्ट्रीयताएं विद्यमान होती हैं, उन तमाम देशों में हम आज भी देखते हैं कि वहां प्रभावशाली उपराष्ट्रीयता (नेशनलिटी) अन्य उपराष्ट्रीयता या उपराष्ट्रीयताओं का उत्पीड़न करती जा रही है। हमारे देश के समाज के स्वरूप और चरित्र में भी इसकी स्पष्ट झलक मिलती है। राजनैतिक तौर पर एक राष्ट्र बन जाने के बावजूद सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से विचार करने पर देखा जायेगा कि हम विभिन्न जन समूहों और समुदायों के जमावड़े के सिवा और कुछ नहीं हैं। हम धर्म, भाषा, नस्ल और जात-पात को केन्द्र कर एक-दूसरे से आपस में बंटे हुए हैं।

...अगर सामाजिक जीवन में जनवादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना है, तो जो लोग 'जनतंत्र' के नाम पर हो-हल्ला मचा रहे हैं, उनका प्रधान कर्तव्य यह होना चाहिए था कि वे सबसे पहले शिक्षा को धर्म के प्रभाव से मुक्त करते। लेकिन इसके पूरी तरह से उलट हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा के साथ धर्म को जोड़ने का एक रुझान हम हाल-फिलहाल देख रहे हैं। इसके नतीजतन धार्मिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, जिसका मकसद है हमारे देश की प्रतिक्रियावादी ताकतों के हितों की बेहतर ढंग से पूर्ति करना। धार्मिक परम्परा के समक्ष इस तरह से आत्मसमर्पण करने की वजह से जनतंत्र संबंधी तमाम घोषणाएं वास्तव में लफ्फाजी बनकर रह गयी हैं। इसलिए इस स्थिति में हमारे देश की इस शिक्षा व्यवस्था के नतीजे के तौर पर संकीर्णता, साम्प्रदायिकता और जात-पात के प्रति जो साफ रुझान देखा जा रहा है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है।

... अतएव हमारे देश की बुर्जुआ जनवादी क्रांति या राष्ट्रीय जनवादी क्राति के लम्बे अर्से से अधूरे पड़े कार्यभारों को पूरा करना यानी सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति को अंजाम देने के लिए जनता के जनवादी आन्दोलनों को ताकतवर बनाना ही हमारे देश की शिक्षा सुधार का मुख्य उद्देश्य है।''

सच है कि इस भेदभावकारी मानसिकता को खत्म करते हुए समाज में जनवादी मूल्यबोध को लाने का संघर्ष हमारे देश में आजादी के पहले भी अपनी जड़ नहीं जमा पाया और आजाद भारत में भी सत्ता संभालने वालों द्वारा कभी इसकी कोशिश नहीं हुई। हमारे देश में नवजागरण काल के मनीषियों और आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महानायकों ने जात-पात, धर्म, भाषा व क्षेत्र के आधार पर जनता में व्याप्त विभाजनकारी मानसिकता को समाज के जनवादीकरण की मुहिम द्वारा दूर करने की, जनता में जनवादी मूल्यबोध पैदा करने की, सामाजिक-सांस्कृतिक मुहिम द्वारा व शिक्षा के जरिये छात्र-नौजवानों में वैज्ञानिक, तर्कसंगत विचार व आचरण निर्मित करने की जो कोशिश की थी, अफसोस की बात है कि आजादी के बाद शासक पूंजीपति वर्ग ने इसे लगातार कमजोर करने की कोशिश ही की। अपने सत्ता पर बने रहने के स्वार्थ में उन्होंने जनता की एकता में दरार कायम रखना ही जरूरी समझा। आजादी के बाद आयीं तमाम राजनैतिक पार्टियों ने न केवल सामंती सोच पालने-पोसने का काम किया, बल्कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इसे बढ़ावा दिया। न केवल जातिगत मानसिकता को, बल्कि धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग सभी को अपनी वोट की ओछी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। आज चाहे यूजीसी हो या भाजपा सरकार, क्या सच में वे भेदभाव व उत्पीड़न को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल यही भाजपा सरकार जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर आई और जिसका विरोध पूरे देश का प्रगतिशील तबका कर रहा है, उसकी एक प्रमुख वजह यह भी है कि यह नीति धर्म, भाषा आदि के आधार पर भेदभाव को बढ़ाने का काम कर रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पर अंधराष्ट्रवाद, धार्मिक व जातीय कट्टरता, अवैज्ञानिक चिंतन और सामंती सोच-विचार को शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है और नवजागरण तथा आजादी आंदोलन के उन तमाम महान मनीषियों के विचारों को पाठ्यक्रमों से दरकिनार किया जा रहा है, जिन्होंने इस तरह की सामंती कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष चलाकर जनवादी चिंतन व सामाजिक एकता की मुहिम चलायी थी। फिर इस सरकार से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह भेदभाव को खत्म करने का कार्य करेगी, जिसकी नींव ही विभाजन पर खड़ी है! जो छात्र संघ संस्थानों में तमाम तरह के भेदभावों से ऊपर उठकर छात्रों की अपनी स्वतंत्र और एकताबद्ध पहचान को सामने रखते हुए छात्रों, संस्थानों व शिक्षा और समाज की समस्याओं को लेकर मुखर रहते थे और जिनके आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के जरिये छात्रों के बीच और संस्थान में एक जनवादी माहौल तैयार करने की कोशिश रहती थी, उन्हें लगभग खत्म किया जा चुका है। छात्र संघ चुनावों पर पाबंदियां लगाकर या तो उसे संस्थानों में बंद किया जा चुका है या उसे महज दिखावा बनाकर छोड़ दिया गया है। ऐसे में 'भेदभाव' को खत्म करने की बात करते हुए यूजीसी रेगुलेशन को लाना मन में स्वाभाविक संदेह पैदा करता है, जिसे हम सभी छात्रों, शिक्षकों सहित आम जन को समझने की जरूरत है।

हम समझते हैं कि शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव व उत्पीड़न के विरोध में पैदा हुए देशव्यापी विरोध ने यूजीसी को यह रेगुलेशन लाने के लिए मजबूर किया। लेकिन अपनी चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सरकार अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इसका फायदा उठा रही है। इस रेगुलेशन को सामने रखते हुए सरकार ने एक तरफ अनुसूचित जाति-जनजाति के साथ-साथ अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों तथा अन्य लोगों का समर्थन लेने की कोशिश की और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा रेगुलेशन पर रोक का फैसला आने के बाद जब उच्च वर्ग के छात्र तथा लोग खुश हो गए, तो अब सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के सामने 'हम क्या करें!' का भाव प्रदर्शित कर रही है, मानो रेगुलेशन पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। यह गौरतलब है कि जो सरकार अपने खिलाफ किसी भी तरीके से आवाज उठाने वाले को 'एण्टी नेशनल' के खिताब से नवाजती है और उस पर काले कानून थोपकर और उसे जेल में डालकर यह जता देती है कि 'विरोध करना मना है', उसी सरकार के खिलाफ पूरे देश में हो रहे इतने उग्र विरोध के मामले में सरकार चुप्पी साधे रहती है और अप्रत्यक्ष तौर पर उसे फैलने देती है। इस तरहे से भाजपा सरकार जातिगत भावना को उकसाकर सभी समुदायों के लोगों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश में जुटी हुई है। सत्ताधारी वर्ग की इस प्रकार की राजनीति के बारे में सचेत करते हुए भारतीय आजादी आंदोलन की गैरसमझौतावादी धारा के क्रांतिकारी शहीद-ए-आजम भगत सिंह ने अपने लेख 'अछूत समस्या' में लिखा था- ''...तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जायेगा। तुम असली सर्वहारा हो... संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ भी हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरें कट जायेंगी। उठो, और वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध बगावत खड़ी कर दो। धीरे-धीरे होनेवाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आन्दोलन से

(शेष पृष्ठ 6 पर)

रसोई गैस के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार ने महंगाई की मार से परेशान लोगों पर डाला भारी बोझ

देश के लोग पहले से ही महंगाई की मार से परेशान हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने उस पर रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का बोझ डाल दिया। युद्ध के बहाने गैस सिलेंडर की कीमत 60 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दी गई। वाणिज्यिक सिलिंडर पर 114.50 रुपये की वृद्धि की गई है। भाजपा सरकार ने पिछले साल अप्रैल में ही रसोई गैस की कीमतें 50 रुपये बढ़ा दी थीं। हालांकि ईरान पर अमेरिकी-इजराइल हमले की शुरुआत के बाद से ही सरकार की ओर से आश्वासन दिये जा रहे थे कि देश में गैस-तेल की कीमतें बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। सरकार ने दावा किया था कि देश में 3-4 सप्ताह के लिए आवश्यक मात्रा में गैस का भंडार है। इसलिए अगर यह सच है, तो सरकार ने एक सप्ताह के भीतर ही इसके दाम क्यों बढ़ाये?

इसके अलावा, सरकार ने कथित तौर पर सभी सरकारी और निजी तेल शोधन कारखानों को गैस उत्पादन में अधिकतम वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अमेरिका के साथ हुए समझौते के अनुसार गैस आनी शुरू हो गयी है। तो फिर इतनी जल्दबाजी में गैस के दाम क्यों बढ़ाये गये? लेकिन क्या यह मूल्य वृद्धि अमेरिकी दबाव के आगे झुकने और महंगी गैस आयात की लागत को संभालने के लिए की गई है? या युद्ध को बहाना बनाकर देश के एकाधिकारी पूंजीपतियों को अतिरिक्त लाभ कमाने का अवसर देने के लिए? 2015-16 में, देश में गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 33.3 करोड़ थी। इस भारी मूल्य वृद्धि के कारण सिलिंडर पर कंपनियों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा।

स्वाभाविक है कि इस मूल्य वृद्धि से पूरे देश के आम लोगों में भारी रोष व्याप्त है। हर जगह सवाल उठ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ वर्षों में जब तेल-गैस के दाम गिर गये हैं, तब भी सरकार ने घरेलू बाजार में इन सभी वस्तुओं के दाम कम नहीं किये। सरकार ने कहा कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दाम बढ़ने के बावजूद घरेलू बाजार में ईंधन तेल-गैस के दाम नहीं बढ़ाये जा रहे हैं। तो अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने के साथ-साथ सरकार ने इतने दाम क्यों बढ़ाये? लंबे समय से जिन कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सस्ते दामों का लाभ उठाकर भारी मुनाफा कमाया है, उन पर अब थोड़ा-सा बोझ क्यों नहीं डाला गया? इसके अलावा, प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के छोटे-बड़े नेता तक, दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जो गौरव महसूस करते हैं, क्या वास्तव में उनके पास इतनी मूल्य वृद्धि का भार उठाने की क्षमता भी नहीं है? इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने पिछले साल सितंबर तक पांच साल में बड़े पूंजीपतियों के 6 लाख करोड़ रुपये के बैंक ऋण खाते को खातों से हटा दिया। वह सरकार देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त आम लोगों को खजाने से मामूली राहत क्यों नहीं देगी? प्रधानमंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों और नौकरशाहों की विदेश यात्राओं, फिजूलखर्ची और विलासिता के खर्चों में कटौती के बावजूद, सरकार ने जनता को मूल्य वृद्धि के संकट से कुछ राहत क्यों नहीं दी? तो क्या किसी को यह समझने में कोई कठिनाई है कि यह सरकार किसके लिए काम कर रही है-पूंजीपतियों के लिए या जनता के लिए?

भारत के तेल-गैस पोत भी ईरान की बंदरगाहों से गुजरने से रोक दिये गए हैं, क्योंकि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों के जहाजों को बंदरगाहों से गुजरने से रोक दिया है। ईरान भारत का एक पुराना मित्र है। भारतीय एकाधिकारी पूंजी के हित में अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए, यहां तक कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की हत्या की निंदा करने के लिए भारत सरकार को शोक व्यक्त करने में लगभग एक सप्ताह का समय लगा! सरकार ने नियमों के उल्लंघन के लिए लोगों की कड़ी आलोचना का सामना किया है। वास्तव में, भारत सरकार अमेरिकी साम्राज्यवाद की ओर ज्यादा से ज्यादा झुक रही है ताकि भारतीय एकाधिकार पूंजीपतियों के लिए अमेरिका-इजराइल की लूट का बकरा सुनिश्चित किया जा सके। क्योंकि साम्राज्यवादी लूट के लिए भारतीय पूंजीपतियों को अमेरिकी पूंजीपतियों के हाथ पकड़ने की जरूरत थी, जो मध्य और दक्षिण-पूर्व एशिया के बाजारों में थीं। भारत सरकार देश के लोगों के हित और बुरे से बुरे के लिए दुनिया में भारत के साथ ऐतिहासिक रूप से मित्र देशों के साथ खड़े होने के कर्तव्य से मुकर गयी।

अगर युद्ध कुछ और समय तक चला, तो शायद यह भी पता चलेगा कि सरकार ने ईंधन तेल-गैस के दाम भी बढ़ा दिये हैं। क्योंकि पूंजीवादी वर्ग के हित साधने लिए प्रतिबद्ध इस सरकार ने जनता से जो भी वादा किया है, वह विश्वसनीय नहीं है। ऐसे में, ईंधन गैस के दामों में बढ़ोतरी के बहाने रोजमर्रे की जरूरत की चीजों के दाम बढ़ जायेंगे और जनजीवन को और भी कष्टप्रद बना देंगे। लेकिन युद्ध के शासकों और पूंजीपतियों की लूट के क्षेत्र के बीच आम लोगों का जीवन और अधिक संकटग्रस्त क्यों होगा? इसलिए रसोई गैस के दामों में की गयी बढ़ोतरी तत्काल वापस लेने, पर्याप्त सरकारी सब्सिडी के साथ महंगाई की मार से लोगों को बचाने और किसी भी बहाने के बिना ईंधन तेल और रसोई गैस के दाम न बढ़ाने की मांग के लिए देश के लोगों को आवाज बुलंद करनी होगी।

पश्चिम बंगाल ...

(पृष्ठ 2 का शेष)

नष्ट करने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार भी व्यवहारतः इसी शिक्षा नीति को लागू कर रही है। घोर भ्रष्टाचार, कुशासन और निकम्मेपन में डूबी हुई राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के साथ मजदूरों, किसानों और आमजनों के हितों के खिलाफ काम करने वाली केन्द्र की सत्ता पर काबिज फासीवादी भाजपा में चेहरे और शक्ति के न्यूनाधिकता के सिवा कोई मौलिक अंतर नहीं है। पूंजीपति वर्ग द्वारा संचालित मीडिया ने बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार चलाकर सत्ताधारी वर्ग के हित साधने वाली दोनों पार्टियों के बीच घोर ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया है। जनता को व्यवहारतः उबलते तेल की कड़ाही या जलते हुए चूल्हे में से किसी एक में कूदने के विकल्प को चुनने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

दूसरी ओर, जब केन्द्र और राज्य की सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ एक जोरदार वामपंथी आन्दोलन खड़ा करने की जरूरत थी, तब सीपीआई (एम) सहित वामपंथी के रूप में जाने जाने वाली पार्टियों की भूमिका काफी अफसोसजनक है। जिस कांग्रेस सरकार के खिलाफ लम्बी लड़ाई लड़कर वामपंथी आन्दोलन को मर्यादा और गौरव प्राप्त हुआ था, उसी कांग्रेस के साथ मात्र कुछ सीटों के लिए पूरे देश में और इस राज्य में एकता कायम करने की कोशिश सहित सांप्रदायिक ताकत के साथ एकता कायम की गयी है। इससे वामपंथी विचारधारा वाले अनेक लोग आहत हुए हैं।

एसयूसीआई (सी) केन्द्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जन आन्दोलन और वर्ग संघर्ष गठित करने के मकसद से मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं के आधार पर जनता की अपनी राजनैतिक शक्ति जन कमेटियों के निर्माण में लगी हुई है। मार्क्सवाद-लेनिनवाद-शिवदास घोष की क्रांतिकारी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर इस संघर्ष के जरिये हमने अनेक मांगें हासिल की हैं। हम कई गलत कामों को रोकने में कामयाब हुए हैं। आरजी कर अस्पताल की पीड़िता को न्याय दिलाने सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन, राज्यभर में महिला उत्पीड़न के खिलाफ आन्दोलन, आशा कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक लगातार हड़ताल, विनाशकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द कराने के लिए राष्ट्रव्यापी आन्दोलन, स्मार्ट मीटर लगाये जाने के खिलाफ बिजली आन्दोलन, देशव्यापी किसान आन्दोलन आदि अनगिनत जन आंदोलन खड़े करने में देशभर में, राज्य में और क्षेत्रीय स्तर पर हमारी पार्टी ने कहीं प्रत्यक्ष रूप से तो कहीं जन कमेटियों के जरिये अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। इसी आन्दोलन के एक हिस्से के रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं कि जन आन्दोलन की एक भरोसेमंद ताकत के रूप में आप हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देकर विजयी बनाते हुए जनजीवन की ज्वलंत समस्याओं के निदान के संघर्ष को तेज करें।"

अमेरिका से किये गये जनविरोधी, किसान-विरोधी व्यापार समझौते के खिलाफ जोरदार किसान आन्दोलन खड़ा करने का एआईकेकेएमएस ने किया आह्वान

रोहतक (हरियाणा)

ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) के नेता-कार्यकर्ताओं की एक राज्य स्तरीय बैठक 2 मार्च को स्थानीय हुडा सिटी पार्क में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संगठन के राज्याध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह मातनहेल ने की। संचालन राज्य सचिव कॉमरेड जयकरण मांडौठी ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान एवं महासचिव कॉमरेड शंकर घोष ने कहा कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के कारण मेहनतकशों के जीवन की समस्याएं दिनों-दिन बढ़ रही हैं। अभी हाल में हुए अमेरिका-भारत व्यापार समझौते में देश के बड़े-बड़े कॉरपोरेट पूंजीपति घरानों के स्वार्थ में किसान-खेत मजदूरों सहित आम लोगों के हितों की बलि दी गई है। एआईकेकेएमएस इसका कड़ा विरोध करता है। कॉरपोरेट घरानों के हित साधने के लिए बीज बिल-2025 लाकर परंपरागत खेती को किसानों के हाथों से छीनने का जाल बिछा दिया गया है। आनुवांशिक बीज (जीएम सीड्स) खेती को उजाड़ने वाला है। एमएसपी की मांग लंबित है। किसान-मजदूर कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। बिजली बिल 2025 के माध्यम से बिजली मामलों का पूर्ण रूप से निजीकरण किया जा रहा है। मनरेगा कानून को खत्म कर भूमिहीन खेतमजदूरों व अन्य ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार के बचे-खुचे अवसर भी समाप्त कर दिये गये हैं। हरियाणा रोडवेज का भट्ठा बैठा दिया गया है। प्राइवेट बसों में बुजुर्गों का आधा किराया और विद्यार्थियों को बस पास सुविधा सरकार की मिलीभगत से समाप्त कर दी गई है। सरकार की मंशा बुढ़ापा पेंशन को छीनने की है। अरावली पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जा रहा है।

संगठन ने फैसला लिया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे प्रदेश में जोरदार जन जागृति अभियान चलाया जाएगा।

बैठक में आमन्त्रित एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने हरियाणा सरकार के बजट को जनविरोधी करार दिया।

इस बैठक में रोहतक, झज्जर भिवानी, हिसार, सोनीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रेवाड़ी इत्यादि जिलों से किसान नेताओं ने हिस्सा लिया।

बिजली विधेयक 2025, बिजली के निजीकरण व प्रीपेड स्मार्ट मीटर के विरोध में प्रदर्शन

भोपाल, मध्य प्रदेश।

बिजली विधेयक 2025, बिजली के निजीकरण व प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध दिवस पर मध्य प्रदेश बिजली उपभोक्ता एसोसिएशन की भोपाल इकाई द्वारा 10 मार्च को स्थानीय प्रभात चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया गया।

एसोसिएशन के भोपाल प्रभारी विनोद लोगरिया ने कहा कि बिजली विधेयक 2025 बिजली के निजीकरण का प्रारूप है। यह बिजली को मुनाफे की वस्तु में बदलकर मुनाफा लूटने के लिए मध्य प्रदेश का बिजली क्षेत्र बड़े कॉर्पोरेटों के लिए खोल देगा। प्रीपेड स्मार्ट मीटर टीओडी के नाम पर उपभोक्ताओं की जेब खाली करने वाले हैं। ये बिजली के बिल बेतहाशा बढ़ा रहे हैं। लोग इनसे परेशान है और बिजली कंपनी बिना उपभोक्ताओं की अनुमति के जबरदस्ती प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाती जा रही है।

हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने गली-मोहल्ले, गांव-शहरों में जन कमेटियों गठितकर बिजली के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन तेज करने की सभी से अपील की।

प्रदर्शन का संचालन आरती शर्मा ने किया।

जंगखोर अमेरिका-इजरायल गठजोड़ द्वारा ईरान पर किये गये हमले के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन

बलिया, उत्तर प्रदेश।

जंगखोर अमेरिका-इजरायल गठजोड़ द्वारा ईरान पर किये जा रहे बर्बर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (सी) जिला कमेटी बलिया की ओर से 2 मार्च को नगरा नगर पंचायत, बलिया के गड़वार मोड़ से जुलूस निकाला गया, जिसे पुलिस बल ने रोक दिया और पार्टी कार्यकर्ताओ से बीच सड़क पर वार्ता की। जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओ ने अमेरिका व इजरायल के खिलाफ जोरदार ढंग से नारे लगाये।

कार्यक्रम में एसयूसीआई (सी) के बलिया जिला सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र कुमार सहित कई लोग शामिल हुए।

बदलापुर, जौनपुर,उ.प्र।

साम्राज्यवादी अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर किये गये बर्बर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) की जिला कमेटी जौनपुर की ओर से 1 मार्च को बदलापुर क्षेत्र के अन्तर्गत कुशहां बाजार में विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन को एसयूसीआई (सी) के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड रविशंकर मौर्य, कॉमरेड अशोक कुमार खरवार, कॉमरेड इंदुकुमार शुक्ल व कॉमरेड प्रमोद कुमार शुक्ल ने सम्बोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कॉमरेड संतोष कुमार प्रजापति ने किया।

पटना, बिहार।

1 मार्च को पटना के बुद्ध स्मृति पार्क पर एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) ने अमेरिका इजरायल गठजोड़ द्वारा ईरान पर हमले के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाये–'जंगखोर अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली साम्राज्यवाद गठजोड़ द्वारा ईरान पर युद्ध अविलंब रोको', 'पूंजीवाद-साम्राज्यवाद मुर्दाबाद', 'इजरायल ईरान से दूर हटो', 'युद्ध नहीं शांति चाहिए', 'भारत सरकार इजरायल से सभी तरह के राजनयिक संबंध विच्छेद करो'।

इस मौके पर वक्ताओं में प्रमुख रूप से पार्टी के बिहार राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड साधना मिश्रा, कॉमरेड अर्जुन कुमार, कॉमरेड सूर्यकर जितेंद्र, कॉमरेड अनामिका कुमारी, कॉमरेड अर्चना अपराजिता शामिल थे।

रोहतक, हरियाणा।

'साम्राज्यवादी अमेरिका व इजरायल गठजोड़ मुर्दाबाद', 'ईरान पर हमले बंद करो', 'युद्ध नहीं शांति चाहिए', 'ईरान के नेताओं और जनता का कत्लेआम बन्द करो' इत्यादि नारों के साथ ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने 2 मार्च को स्थानीय सिटी पार्क के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। किसान संगठन के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड अनूप सिंह एवं कॉमरेड जयकरण मांडौठी ने इसका नेतृत्व किया।

एआईकेकेएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान एवं महासचिव कॉमरेड शंकर घोष एवं एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड राजेंद्र सिंह सहित अच्छी खासी संख्या में लोग उपस्थित थे।

गुरुग्राम, हरियाणा।

अमेरिका-इजराइल साम्राज्यवादी गठजोड़ द्वारा ईरान पर किये जा रहे बर्बर हमलों के खिलाफ 1 मार्च को यहां के डाकखाना चौक पर विरोध प्रदर्शन और अमेरिकी साम्राज्यवाद

का पुतला दहन किया गया।

सभा का संचालन कॉमरेड वजीर सिंह ने किया। सभा का एआईयूटीयूसी के जिला सचिव कॉमरेड श्रवण कुमार गुप्ता, इंकलाबी मजदूर केंद्र के कॉमरेड राजू, बेल सोनिका यूनियन के महासचिव कॉमरेड अजित सिंह तथा एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के जिला सचिव कॉमरेड बलवान सिंह ने संबोधित किया।

नारनौल, हरियाणा।

अमेरिका-इजराइल साम्राज्यवादी गठजोड़ द्वारा ईरान पर किये जा रहे बर्बर हमलों के खिलाफ 3 मार्च को यहां विरोध प्रदर्शन कर और साम्राज्यवाद का पुतला दहन कर युद्धोन्मादी नीतियों की कड़ी निंदा की गई।

इस कार्यक्रम में किसान नेता कॉमरेड बलबीर सिंह, कॉमरेड सीताराम प्रधान समेत अनेक सचेत नागरिकों ने हिस्सा लिया।

भिवानी, हरियाणा।

इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान से किये गए बर्बर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के जिला सचिव कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी के नेतृत्व में 2 मार्च को तोशाम के सुरेन्द्र चौक पर अमेरिकी और इजरायली राष्ट्रपति का पुतला दहन किया गया।

सोनीपत, हरियाणा।

इजरायल-अमेरिका द्वारा ईरान पर किये गए बर्बर हमले के खिलाफ एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड ईश्वर सिंह राठी के नेतृत्व में 1 मार्च को ककरोई रोड़, सोनीपत में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पुतला दहन किया गया। डॉक्टर सत्यपाल रांगी ने पुतले को आग लगाई।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मेहनतकश महिलाओं ने शोषणहीन समाज का सपना साकार करने का संकल्प दोहराया

दिल्ली।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 15 मार्च को सोनिया विहार में इस युग के प्रमुख मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड शिवदास घोष की कृति 'महिला मुक्ति का रास्ता' पर एक परिचर्चा आयोजित की गयी। मुख्य वक्ता थीं एआईएमएसएस की अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड केया डे। महिलाओं पर बढ़ते अपराध, शराब और पोर्न साइटों पर रोक लगाने के लिए मोदी सरकार की ओर से कोई भी पहलकदमी न करने के कारण सरकार की तीखी आलोचना करते हुए उन्होंने महिलाओं को खुद ही संगठित होकर आगे आने का आह्वान किया। हर तरह के शोषण से मुक्त समाज बनाने के लिए उन्नत नीति-नैतिकता के आधार पर सामाजिक-सांस्कृतिक आंदोलन गठित करने के काम को ऐतिहासिक जरूरत बताते हुए उन्होंने प्रेरणादायक वक्तव्य रखा।

एआईएमएसएस की दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सीता सिंह, उपाध्यक्ष पुष्पा चमोली, नीतू खन्ना, राज्य सचिव कॉमरेड रितु कौशिक, सचिवमंडल सदस्य कॉमरेड आशा रानी और कॉमरेड सुनिधि ने भी अपने विचार रखे।

अंत में एसयूसीआई (सी) के पूर्वी दिल्ली जिला कमेटी सदस्य कॉमरेड सतीश पवार ने परिचर्चा में सारगर्भित चर्चा रखी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ परिचर्चा का समापन हुआ।

रेवाड़ी, हरियाणा।

8 मार्च–अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्थानीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में ऑल इण्डिया महिला सांस्कृतिक संगठन (एआईएमएसएस) एवं स्कीम वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में सभा का आयोजन

किया गया, जिसमें काफी संख्या में महिलाओं ने गांवों एवं शहर से हिस्सा लिया।

सभा का संचालन एआईएमएसएस की जिला सचिव कॉमरेड संतोष ने किया। सभा में कई वक्ताओं ने अपनी बातें रखीं। सभी ने एक स्वर में आवाज उठायी कि महिलाएं अबला नहीं, इंसान हैं। बच्चियों एवं महिलाओं पर बढ़ते जुल्म-अत्याचारों, अपराधों, अश्लीलता व नग्नता, शराबखोरी और नशाखोरी पर रोक लगायी जाए। उन्होंने महिलाओं के हो रहे दोहरे शोषण के

खिलाफ जोरदार आंदोलन की जरूरत पर बल दिया। अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा देने और जिला स्तर पर फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की मांग भी की गई।

सभा के मुख्य वक्ता केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह एडवोकेट ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कामकाजी महिलाओं के लिए अपने हक-हकूक हासिल करने के लिए और शोषण-जुल्म व भेदभाव को खत्म करने के लिए आंदोलन को तेज करने की अहद लेने का दिन है। वहीं महिलाओं को शोषित-पीड़ित जनता का अभिन्न अंग होने के नाते जनआंदोलनों में सक्रिय हिस्सा लेने और अपने संघर्ष को शोषणहीन समाज बनाने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है।

PRGI Regn. No. 43022

मणिपुर समस्या : विवाद कायम रखना ही भाजपा का लक्ष्य

एक वर्ष बीत जाने के बाद अंतत: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त कर भाजपा ने मुख्यमंत्री पद पर युमनाम खेमचंद सिंह को बैठाया है। उपमुख्यमंत्री बने हैं दो भाजपा विधायक नेमचा किपजेन और नागा पीपल्स फ्रंट के विधायक लोसी दिखो। नेमचा कुकी जनजाति की महिला हैं और दिखो नागा जनजाति से आते हैं। दूसरी ओर खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के हैं। ऐसा लग सकता है कि मणिपुर में मैतेई और कुकियों जैसे परस्पर विरोधी दो समुदायों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल में शामिल कर भाजपा तथा केंद्र सरकार ने ढाई वर्षों से चल रहे रक्तरंजित सामुदायिक संघर्ष को समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाया है।

कम नहीं हुआ विरोध

लेकिन विरोध समाप्त होने के बजाय देखा गया कि मंत्रिमंडल गठन के बाद विधानसभा में सरकार के विश्वासमत पाने के दिन कोई भी कुकी-जो जनजाति का विधायक उपस्थित नहीं हुआ। सरकार का समर्थन करने वाले तीन कुकी विधायकों ने वर्चुअल माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। विश्वासमत से कुछ दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री की देखरेख में उन्हें विमान से दिल्ली ले जाया गया और विश्वासमत से ठीक पहले फिर दिल्ली से सीधे विमान द्वारा इम्फाल लाया गया। उल्लेखनीय है कि ढाई साल बाद मणिपुर के कुकी जनजाति के किसी विधायक को विधानसभा तक ले जाने का साहस सरकार नहीं कर सकी। भाजपा सरकार ने विधानसभा में विधायकों से विश्वासमत तो मांगा, लेकिन अपने प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर भरोसा नहीं किया। कुकी-जो क्षेत्र से चुने गए 10 विधायकों में से केवल तीन की उपस्थिति से जनजातियों के सरकार पर विश्वास का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। उसी दिन चुराचांदपुर और कांगपोकपी सहित कई पहाड़ी जिलों में तीव्र विरोध शुरू हो गया। कुकी-जो जनजाति के सात संगठनों के संयुक्त मंच ने सरकार का समर्थन करने वाले तीन भाजपा विधायकों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया। जनजाति क्षेत्र में अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग को लेकर यह मंच संघर्ष कर रहा है। इन विधायकों के काम को उन्होंने जनजातियों से विश्वासघात करार दिया। पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर तीन विधायकों के पुतले जलाये गए। नई जगहों पर विरोध और संघर्ष शुरू होने की खबरें आयी हैं। इसके अलावा, नागाओं और कुकियों के बीच भी कुछ जगहों पर संघर्ष की खबर मिली है।

सामुदायिक संघर्ष खत्म करने का सरकार ने नहीं किया प्रयास

मणिपुर का वर्तमान संघर्ष मैतेई समुदाय को 'अनुसूचित जनजाति' (एसटी) मानने के हाईकोर्ट के निर्णय से शुरू हुआ। इस निर्णय से कुकी और नागा जनजातियों में आशंका पैदा हुई कि अगर मैतेई अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल हो गए, तो पहले से ही सीमित शिक्षा और रोजगार बाजार में आरक्षित सीटों के दावेदार बढ़ जायेंगे। जबकि निर्णय के बाद संघर्ष शुरू होने से पहले सरकार के पास जनजातियों के आक्रोश को शांत करने के लिए एक महीने से अधिक समय था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठा कि हाईकोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे रहा था, फिर भी राज्य सरकार के वकीलों ने यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? भाजपा के केंद्रीय नेताओं की मर्जी के बिना क्या यह संभव था? जघन्य जातीय संघर्ष में लगभग 250 लोगों की जान गई। कई हजार घायल हुए। 60 हजार लोग बेघर होकर शरणार्थी शिविरों में दिन बिता रहे हैं। इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी क्षेत्रों के कुकी-जो, जोमी, हमर आदि आदिवासियों के बीच शत्रुता इतनी बढ़ गई है कि एक समुदाय का व्यक्ति दूसरे समुदाय के क्षेत्र में जाए, तो जान जाने का खतरा रहता है। इम्फाल में स्थित सरकार को पहाड़ी आदिवासी लोग मैतेइयों की सरकार मानते हैं। दूसरी ओर भाजपा सरकार के ज्यादातर मंत्री भी यही मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बीरेन सिंह भी स्वयं को मैतेई का मुख्यमंत्री कहलाना पसंद करते थे। प्रशासन और सरकार का यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार समस्या को और जटिल बना रहा है।

मणिपुर जैसे राज्य में जहां लंबे अर्से से जातीय शत्रुता का इतिहास रहा है, वहां उदारता, विवेक और धर्म-जाति-समुदाय के मामलों में पूरी तरह निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर पूरे मामले का समाधान करना आवश्यक था। लेकिन आजादी के बाद से केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और बाद में भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया। इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय के लोग मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 53 प्रतिशत हैं। 60 सीटों वाली विधानसभा में उनके पास 40 सीटें हैं। कांग्रेस ने कभी सत्ता पाने के लिए इनका तारणहार बनना चाहा। ब्रिटिश शासन के अधीन राजशाही राज्य होने के कारण मणिपुर भारतीय आजादी आंदोलन की मुख्य धारा से बाहर था। 1949 में उसका भारत में विलय हुआ। मणिपुर के लोगों की अस्मिता की समस्या को ध्यान में रखते हुए आजाद भारत के संविधान में धारा 371-सी जोड़ी गयी थी। इसमें राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष समिति बनाने और वहां के लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकार दिये गये थे। इस धारा को सही ढंग से लागू कर मणिपुर के सभी हिस्सों के लोगों का विश्वास अर्जित करना आवश्यक था। पहाड़ और घाटी दोनों क्षेत्रों में पिछड़ापन था, लेकिन पहाड़ों में समस्या अधिक थी। कृषि, रोजगार के अवसर घाटी की तुलना में पहाड़ों में कम थे। इसलिए सभी हिस्सों के लोगों के रोजगार, राज्य में उद्योग स्थापित करने, कृषि को लाभकारी बनाने, लोगों की आय बढ़ाने, गरीबी दूर करने आदि के लिए जनमुखी दृष्टिकोण से विशेष योजना बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। बल्कि जब भी राज्य के लोग आवाज उठाते, उनका कठोर दमन किया गया। पहाड़ और घाटी दोनों हिस्सों के शोषित लोगों को उन्होंने समझाया कि दूसरे हिस्से के लोग ही उनकी समस्या के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह उन्होंने दोनों समुदायों को एक-दूसरे से लड़ाया।

संघर्ष को बनाये रखना चाहते हैं शासक

मणिपुर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से शासक वर्ग और उनके अनुयायी दल लोगों की अस्मिता की समस्या को उभारते रहे हैं। कभी जनजातीय पहचान, कभी भाषा, कभी धर्म आदि मुद्दों को इस्तेमाल कर शासक वर्ग संघर्ष पैदा करता है। शासक वर्ग यह भुला देकर कि शोषित व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म-जाति-जनजाति-उपजाति का हो, सभी शोषितों की मूल समस्या एक जैसी है, शोषित लोगों को आपस में लड़ाता है। अतीत में कांग्रेस ने यह काम किया, अब भाजपा वही कर रही है। उत्तर-पूर्व के विभिन्न राज्यों में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी भाजपा और तृणमूल जैसी पार्टियां यही कर रही हैं।

लोकतंत्र-पसंद लोग आगे आयें

मणिपुर के लोग देख रहे हैं कि सत्ता-लोलुप चालाक गुटों से लोगों को मुक्तकर सभी जनजातियों की एकता के हित में सीधे आम लोगों का विश्वास जीतने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। यह विश्वास सेना या पुलिस से नहीं मिलेगा। लोगों को समझना होगा कि कौन-से समुदाय को कौन-सा आरक्षण मिल रहा है और कौन-सा नहीं मिल रहा है–इसके चक्र में आपस में लड़कर खून-खराबा करने से शोषित लोगों का ही नुकसान है। इससे सबके लिए काम और रोजगार की मांग पीछे चली जाती है। सभी शोषित लोगों की एकता के आधार पर औद्योगिकीकरण, रोजगार, आर्थिक विकास, जनहित में प्रशासन चलाना आदि जनजीवन की मूल मांगें पूरी कराने के लिए लोकतांत्रिक संघर्ष ही रक्तरंजित सामुदायिक तकरार का समाधान है। लेकिन शासकों में कहीं भी जनमुखी और पूरी तरह सामुदायिक-निरपेक्ष दृष्टिकोण आज बिल्कुल नहीं है–यह सच्चाई मणिपुरी लोगों को अपना खून बहाकर समझनी पड़ रही है।

आज किसी भी बुर्जुआ राजनीतिक ताकत में यह दृष्टिकोण नहीं है, यहां तक कि वामपंथी पेटी बुर्जुआ राजनीतिक ताकतों में भी नहीं। आज जनवादी आंदोलन के मंच से यह मांग उठानी होगी कि सरकार को निश्चित रूप से निष्पक्ष रहना होगा और इसे लोगों के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सेना के हथियारों के बल पर शांति बनाये रखने का गलत रास्ता छोड़कर सरकार को लोकतंत्र-पसंद नागरिक समाज की सक्रिय भूमिका पर जोर देना होगा। सशस्त्र गुटों को निरस्त्र करने में सरकार को सभी पक्षपात बंद करने होंगे और झूठे आरोप में आम लोगों को परेशान करने पर पुलिस अधिकारियों, सेना के अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों को दंडित करना होगा। और आवश्यकता है मणिपुर के लोगों के जीवन की ज्वलंत मांगों के समाधान के लिए सभी जनवादी ताकतों को एकजुट करना।

लेकिन आज की बुर्जुआ राजनीति की विशेषता ही है कि वह लोगों को विभिन्न हिस्सों में बांटकर, आपस में लड़ाकर उन्हें उलझाये रखती है ताकि आम लोग अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं और उनके कारणों के बारे में सोच ही न सकें। इसलिए भाजपा पानी को गंदा ही बनाये रखना चाहती है ताकि उसका फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा कर सके और सत्ता में बनी रह सके। बुर्जुआ राजनीति करने वाली काई भी अवसरवादी पार्टी इस समस्या को हल नहीं करेगी। मणिपुर सहित पूरे भारत के लोकतंत्र-पसंद व विवेकशील लोगों को आगे आना होगा ताकि केंद्र और राज्य सरकारों पर इस समस्या के समाधान के लिए दबाव बनाया जा सके। ●

निर्माण मजदूरों की हादसे में मौत पर जताया दुख

गुरुग्राम, हरियाणा।

केंद्रीय मजदूर संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) से संबद्ध भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा रजि नं-1845 के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने गुड़गांव के सिधरावली गांव स्थित सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर बीते दिन हुए हादसे में 7 मजदूरों की मौत व अन्य 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल होने पर गहरा दुख जाहिर करते हुए 11 मार्च को जारी बयान में कहा :

"सिधरावली (गुरुग्राम) में हुए निर्माण कार्य के दौरान हादसा बहुत ही दर्दनाक घटना है। प्रदेश में निर्माण कार्यों में जुटे श्रमिक आये दिन ऐसे हादसों के शिकार हो रहे हैं। वे अपंग हो रहे हैं अथवा अपनी जान गंवा रहे हैं। सरकार, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे दर्दनाक हादसे रुकवा पाने में या तो पूरी तरह से विफल हैं या इन हादसों को रोकने में रुचि नहीं ले रहे। ठेकेदार व बिल्डिंग के वास्तविक मालिक मजदूरों की सेहत व उनके जीवन की परवाह किये बगैर मामूली मजदूरी पर उनसे गुलामों की तरह दिन-रात काम ले रहे हैं। मृतक श्रमिकों के परिवार व अपंग हुए श्रमिकों की बाकी जिन्दगी नरक बन जाती है। स्थिति आये दिन बद से बदतर होती जा रही है। भाजपा सरकार ने तो मजदूरों के संघर्षों से हासिल 29 श्रम कानूनों को बदल कर सरमायेदार परस्त 4 लेबर कोड बनाकर उनके बचे-खुचे वैधानिक अधिकार भी छीन लिये हैं। हरियाणा सरकार ने तो निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए एचबीओसीडब्ल्यू की साइट भी बंद कर रखी है। इससे निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण व हितलाभों से उनको वंचित किया जा रहा है।

कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने आगे कहा कि दुर्घटना की जांच-पड़ताल करने, दोषियों के खिलाफ रपट लिखने व पीडितों को न्याय देने के नाम पर खानापूर्ति करके मामले को दबाने, ठंडा करने में यह तिगड़ी तुरंत जुट जाती है। पीड़ितों को वास्तविक राहत व न्याय देने की बजाय सरकारी अमला भी दोषियों को बचाने के रास्ते ढूंढ़ने में ज्यादा रुचि दिखाता है।

भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन हरियाणा सरकार से मांग करती है कि गुरुग्राम की घटना की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच करायी जाए। संबंधित विभागीय अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लाया जाए। दोषियों को जल्द कठोर सजा दी जाए। मृतकों के परिवारों को 50-50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। घायलों का उचित इलाज करवाया जाए व उन्हें 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। सुरक्षा के उचित उपायों किये बगैर श्रमिकों से जोखिम भरे काम न कराये जाए। ऐसी घटना आगे न घटे, इस पर कारगर रोक लगे।

सही लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष...

(पृष्ठ 3 का शेष)

क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम ही तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो। सोये हुए शेरो! उठो और बगावत खड़ी कर दो।'' इसलिए हमें यह समझ लेना होगा कि सरकार की राजनैतिक मंशा इन भेदभावों या उत्पीड़नों को खत्म करने की नहीं है। इसीलिए संगठित और एकताबद्ध छात्र आंदोलन ही इस यूजीसी रेगुलेशन के सही मायने में क्रियान्वयन की गारंटी होगी। यह संघर्ष जात-पात, धर्म, नस्ल, क्षेत्र, भाषा और तमाम भेदभावकारी कारकों से ऊपर उठकर संगठित छात्र समुदाय बनाम शासक सत्ताधारियों का है।

ऐसी परिस्थिति में हमारा स्पष्ट मानना है कि सही धर्मनिरपेक्ष, वैज्ञानिक व जनवादी शिक्षा ही किसी भी देश के शिक्षण संस्थानों में सही ढंग से जनवादी माहौल कायम कर पाने की पहली शर्त हैं। इसीलिए ऐसे किसी भी नियम के क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि महाविद्यालयों-विश्वविद्यालयों में इस जनवादीकरण की प्रक्रिया को तेज किया जाए, कैंपस में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाए, छात्र संघ चुनावों को सुनिश्चित किया जाए और छात्रों के नैतिक व सांस्कृतिक विकास के लिए जरूरी महान विचारधाराओं को उनके सामने रखा जाए। ऐसा करते हुए छात्रों, नौजवानों और आम लोगों को शिक्षा, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा जैसी जीवन से जुड़ी ज्वलंत समस्याओं के खिलाफ एकता कायम करते हुए जनवादी आंदोलनों को मजबूत करना होगा। इस प्रक्रिया के जरिये ही हम छात्र-नौजवानों में जनवादी मूल्यबोध पैदा कर पायेंगे, जो धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय विभाजनकारी मानसिकता से मुक्त हों और वैज्ञानिक, जनवादी व धर्मनिरपेक्ष मूल्यों से लैस हों।

राजनीतिक वित्तपोषण....

(पृष्ठ 1 का शेष)

व उनके कदाचारों के आड़े नहीं आयेंगी। पहले, राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले कॉरपोरेट चंदों को गोपनीय रखा जाता था। लेकिन भाजपा ने 'इलेक्टोरल बॉण्ड' प्रणाली शुरू करके ऐसे लेन-देन को लगभग आधिकारिक बना दिया था, जहां चंदा देने वाले और चंदा लेने वाले दोनों को ही गोपनीयता के पर्दे में रखा जाता है।

थोड़ी-सी भी समझ वाला कोई भी समझ सकता है कि यह बॉण्ड योजना, जो पूरी तरह से अपारदर्शी है, कॉर्पोरेट पैसे, ज्यादातर काले धन को उन पार्टियों की कोष में डालने का एक जरिया है, जो उनके घिनौने वर्ग-स्वार्थ साधने वाली उनकी ताबेदार के रूप में औद्योगिक घरानों की भरोसेमंद पार्टियां हैं। अब यह बात बिना किसी शक-शुब्हा के साबित हो गई है। खुलासे से पता चलता है कि बेचे गए 16,518.11 करोड़ रुपये के बॉण्डों का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ है। जिन विवरणों की जानकारी जनता के लिए उपलब्ध है, उनसे पता चलता है कि यह 'इलेक्टोरल बॉण्ड योजना' आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। मौजूद आंकड़ों के मुताबिक खबर है कि बेचे गये कुल 16,518.11 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉण्डों में से सत्ताधारी भाजपा को 8,250 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2017-2018 और 2022-2023 के बीच बांटी गयी धनराशि का लगभग 57% है।

उस पैसे का इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने या डराने के लिए किस प्रकार किया जाता है? सबसे पहले, पूंजीवाद के अटल नियम के हिसाब से गैर-बराबरी आसमान छू रही है। देश के 95% लोग बढ़ती मुफलिसी में हैं, जबकि 248 अरबपतियों (2025 की रिपोर्ट के अनुसार) के पास कुल मिलाकर लगभग 98 लाख करोड़ रुपये की धन-दौलत है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का एक तिहाई हिस्सा है। दूसरी ओर, बहुत ज्यादा गरीबी, एक ऐसी हालत, जिसमें लोग या परिवार जिंदा रहने के लिए खाना, कपड़ा, रहने को घर और स्वास्थ्य जैसी न्यूनतम बुनियादी जरूरतें तक भी पूरी नहीं कर पाते। भाजपा शासन के इन सालों में ऐसी अपर्याप्त रोटी, कपड़ा, मकान और इलाज की यह बदहाली लगातार बनी हुई है। 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 123 देशों में 102वें नंबर पर है। 25.8 के स्कोर के साथ, देश में भूख की हालत "गंभीर" बतायी गयी है। इसलिए मेहनतकशों की जिंदगी में गंभीर संकट और दु:ख-कलेश बेरोकटोके आगे बढ़ रहा है। लोगों ने देखा है कि सभी सरकारें - चाहे उनके झंडे का रंग-रूप कुछ भी हो-उन्हें लगातार ज्यादा से ज्यादा धोखा दे रही हैं और उनके अधिकारों से उन्हें वंचित करती जा रही हैं। चुनाव से पहले, सत्ता के भूखे नेता और पार्टियां जनता की सेवा करने के बड़े इच्छुक होने का ढोंग करते हैं और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई खोखले वादे करते हैं। चुनाव के बाद, वे सभी वादे झांसे पाये जाते हैं। पूछने पर, सत्तालोलुप बुर्जुआ नेता बड़ी सहजता से कह देते हैं कि ये वादे जुमले होते हैं और चुनाव जीतने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाने जरूरी हैं। जनता ठगा हुआ महसूस करती है और हताश स्वर में कहती है कि 'जो भी लंका जाता है, वही रावण बन जाता है'। ऐसा लंबे समय से चला आ रहा है।

राजनैतिक समझ और पढ़ाई-लिखाई से महरूम ये असंगठित लोग लाचार और बेचारे हैं। उन्हें नहीं पता कि वे सरकारों की दया के पात्र नहीं हैं और न ही उन्हें वोट बटोरू राजनैतिक पार्टियों के लाल-पीली आंखें तरेरने के सामने झुकना है। इसलिए वे मान लेते हैं कि उनकी दुख-तकलीफें और मुश्किलें अब उनकी नियति बन चुकी हैं, जिन्हें कभी बदला नहीं जा सकता। वे यह भी जानते हैं कि चुनाव आते ही ये बुर्जुआ संसदीय पार्टियां पैसों से भरे थैले लेकर आयेंगी और गरीबों के इलाकों-झुग्गी-झोपड़ियों और कच्ची बस्तियों-में नकद पैसे और खाना बाटेंगी। वे मतदान करने को भी एक मामूली रस्म अदायगी समझते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ये लाखों दबे-कुचले लोग सोचते हैं कि जब उन्हें बाद में वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, तो चुनाव से पहले इन सत्ता-लोलुपों द्वारा फेंके गए जो भी टुकड़े मिल रहे हैं, उन्हें ही क्यों न लपक लिया जाये। वे किसी को भी वोट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी एक जैसे ही हैं-किसी को भी आम लोगों की विकट परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं है। इसीलिए चुनाव से पहले बांटे जाने वाले पैसे और सामान को लेने के लिए वे कतारों में लग जाते हैं। अभावग्रस्त लोगों की इसी बेबसी का फायदा उठाकर पैसों के बल पर वोट खरीदे जाते हैं। हजारों रुपये में एक या दस वोट खरीदे जाते हैं। फिर, तरह-तरह की खैरात और मुफ्त की रेवड़ियां भी पेश की जाती हैं। दरअसल, वोट-बटोरू बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ पार्टियां अब आपस में इस बात की होड़ कर रही हैं कि सरकारी खजाने से बेहतर सुविधाओं का लालच देकर वे वंचित तबके को कितना ज्यादा लुभा सकती हैं और उनका वोट बटोर सकती हैं। यह याद रखना जरूरी है कि हमारे माननीय भाजपाई प्रधानमंत्री ने एक बार इस तरह की खैरात बांटने की प्रथा को 'रेवड़ी-राजनीति' कहा था। लेकिन अब, वे और उनकी पार्टी ही चुनाव से पहले और बाद में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने में सबसे आगे हैं।

चुनाव में बहता है बहुत सारा पैसा

अब बात करते हैं कि कैसे प्रशासन तमाशबीन बना रहता है। नियम के मुताबिक, हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के खर्च की ज्यादा से ज्यादा सीमा एक लोकसभा सीट के लिए 95 लाख रुपये और एक विधानसभा सीट के लिए 40 लाख रुपये है। लेकिन चुनावों में कोई भी राजनीतिक पार्टी कितना खर्च कर सकती है, इसकी कोई तय सीमा नहीं है। नियमों के अनुसार, हर राजनीतिक पार्टी को हर चुनाव के बाद अपनी आय-व्यय का हिसाब-किताब जमा करना होता है। लेकिन ऐसे नियम असल में सिर्फ छोटी पार्टियों पर ही लागू होते हैं, जबकि मुख्यधारा की वोट-आधारित पार्टियों को एक अलिखित छूट मिली हुई है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स (एडीआर) ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि पिछले संसदीय चुनाव के दौरान 5 राष्ट्रीय और 27 क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा किये गये धन संग्रह की कुल राशि 7,445.566 करोड़ रुपये थी। इसमें से, 6,268.006 करोड़ रुपये या कुल निधि का 84.18% भाजपा को गया। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों दौरान 32 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर 3,352.81 करोड़ रुपये खर्च किये, जिसमें से 2,204.318 करोड़ रुपये (65.75%) 5 राष्ट्रीय पार्टियों ने खर्च किये। ये सभी उपलब्ध आंकड़े हैं। अनुपलब्ध आंकड़े इनसे कई गुना अधिक होंगे। चुनाव खर्च में अलग-अलग तरह के प्रचार-खर्च शामिल हैं। इनके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, सही भाषा में कहें, तो मतदाताओं को घूस देने के लिए एकमुश्त पैसे का इस्तेमाल किया जाता है।

भाजपा राज ने देश को असल में एक ऐसा बना दिया है, जहां एकाधिकारी पूंजी की बेलगाम लूट बढ़ रही है। लगभग सभी सरकारी उद्यमों-रेलवे, तेल, गैस, बैंक, बीमा, हवाई अड्डे, पहाड़, जंगल, खदानें-यानी देश की धन-दौलत, लोगों की धन-दौलत, सब कुछ चांदी की तस्तरी में सजाकर कॉर्पोरेटों के हवाले कर दिया गया है।

यहां तक कि बड़े-बड़े कारोबारी भी सरकारी खजाने से अलग-अलग रूपों में हथिया लेते हैं - कभी अनुदान के तौर पर, कभी पैकेज के रूप में, तो कभी कर्ज माफी के रूप में।

हाल ही में, टाटा समूह को भाजपा-शासित राज्यों गुजरात और असम में दो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने की मंजूरी मिली। केंद्र सरकार ने इन फैक्ट्रियों के पूंजीगत खर्च का 50% हिस्सा - यानी 44,203 करोड़ रुपये - खुद उठाने की घोषणा की है। इसके कुछ ही दिनों के भीतर टाटा समूह की 15 कंपनियों ने 'प्रगतिशील चुनावी न्यास' को 915 करोड़ रुपये दिये, जिसमें से 758 करोड़ रुपये भाजपा के खाते में गये। इस तरह, भाजपा के कोष में 758 करोड़ रुपये का योगदान देकर टाटा समूह ने सरकारी खजाने से 44,000 करोड़ रुपये अपनी झोली में भर लिये। ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है।

लोगों को न बनने दें इस गंदी राजनीति का शिकार

पूंजीपति अपने प्रबंधकों की मदद से अपना कारोबार चलाते हैं। मंत्री उनके राजनीतिक प्रबंधक बन गये हैं और बुर्जुआ तथा पेटी-बुर्जुआ पार्टियां उनकी आज्ञाकारी प्रजा। इसलिए भले ही सरकार बदल जाए, लेकिन पूंजीपति-परस्त नीतियां नहीं बदलतीं। कॉर्पोरेटों द्वारा राजनीतिक वित्तपोषण पूंजीवादी व्यवस्था की एक ऐसी विशेषता है, जो अब अपनी पतनशील और मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर बीमार पड़ चुकी है। शोषित-पीड़ित आम लोगों से हमारी अपील है कि वे इस गंदी बुर्जुआ राजनीति का शिकार न बनें, बल्कि जरूरी राजनीतिक चेतना हासिल करने की कोशिश करें ताकि वे समझ सकें कि उन्हें कैसे एक 'खरीदी जा सकने वाली जमात' के तौर पर देखा जाता है, कैसे उन्हें 'मुफ्तखोर और लालची लोग' कहकर अपमानित किया जाता है और कैसे उन्हें शोषकों और लुटेरों के सत्ता के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया जाता है।

इसीलिए हमने आने वाले विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर इस पहलू पर फिर से विचार करना जरूरी समझा।

पश्चिम बंगाल में बिजली उपभोक्ताओं की कुछ महत्वपूर्ण मांगें हुईं हासिल

ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएसन (ऐबेका) के नेतृत्व में बिजली उपभोक्ताओं के कड़े विरोध के चलते सरकार ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने का एलान किया था। लेकिन पहले से जोर-जबरदस्ती से लगाये गये स्मार्ट मीटरों को हटाया नहीं जा रहा था। जबकि बढ़ाये गये नियत प्रभार व न्यूनतम प्रभार की मार से राज्यभर के हजारों लघुउद्योग, मसलन गेहूं, धान व तेल की मिलें व प्लास्टिक फैक्ट्रियां पहले ही बंद हो चुकी हैं। किसानों पर टीओडी (टाइम ऑफ डे) मीटर द्वारा खेतों की सिचाई के बढ़े हुए बिल के हजारों रुपये बकाया हैं। इसके खिलाफ ऐबेका के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के कस्टमर केयर सेंटरों से लेकर डिविजनल, रीजनल विद्युत भवनों व हर स्तर के बिजली कार्यालयों पर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

आन्दोलन के दबाव में 19 फरवरी को संगठन के अध्यक्ष और महासचिव के नेतृत्व में पांच सदस्यों के साथ राज्य के बिजली मंत्री की बैठक हुई। मंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालयों को छोड़कर कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं लगाये जायेंगे। उपभोक्ताओं के कहने पर लगाये गये स्मार्ट मीटरों को कंपनी हटाने की व्यवस्था करेगी। संगठन के महासचिव सुब्रत बिस्वास ने कहा कि यह बिजली उपभोक्ताओं के आन्दोलन की जीत है। लघु उद्योगों के लिए न्यूनतम प्रभार को प्रति केवी 200 रुपये से घटाकर 50 रुपये किये जाने के ऐबेका के प्रस्ताव को बिजली मंत्री ने जायज बताया। इस बारे में उन्होंने राज्य की बिजली वितरण कंपनी के वितरक निदेशक को एक लिखित नोट दिया है। ऐबेका की मांग मानते हुए मंत्री ने कहा कि जहां, जो भी बांस के खम्भों पर वैध बिजली कनेक्शन हैं, अगर उनकी फोटो भेज दी जाये, तो उन्हें बदलकर खम्भों का प्रबंध विद्युत भवन से ही कर दिया जायेगा।

कृषि के लिए मुफ्त बिजली की मांग पर मंत्री ने कहा कि हाशिये पर के किसान बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली देने के मामले में पैमाना तय होते ही सरकार इसकी घोषणा करेगी। बातचीत में मौजूद बिजली वितरण कंपनी के वितरक निदेशक ने माना कि सिक्योरिटी डिपॉजिट की मात्रा भार (लोड) के बजाय बिजली की खपत के आधार पर तय होगी। जहां भी भार बढ़ने के बहाने सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़ाया गया है, वहां सहायक दस्तावेजों के साथ शिकायतें वितरक निदेशक को सौंपनी होगी। जरूरत पड़ने पर बिजली मंत्री भी उन दस्तावेजों की जांच करेंगे। हालांकि जिनका वास्तव में भार बढ़ा है, उन्हें अपना भार बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा।

कस्टमर केयर सेंटर के स्तर पर भ्रष्टाचार के प्रसंग में मंत्री ने लिखित शिकायतें प्राप्तकर तत्काल उनकी जांच के आदेश दिये हैं। बिजली मंत्री ने बताया कि अगर केंद्र सरकार जनविरोधी बिजली कानून संशोधन विधेयक 2025 पारित भी कर देती है, तो भी उसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जायेगा।

ऐबेका की ओर से बताया गया है कि बिजली का शुल्क (टैरिफ) कम से कम 16.5 प्रतिशत लाभ रखकर ही तय किया जाता है। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अगर कैप्टिव कोल माइंस से कोयला निकाला जाता है, तो बिजली की कीमत निश्चित रूप से घट जायेगी। इसलिए बिजली शुल्क में 50 प्रेतिशत की कमी करने की वास्तविक स्थिति मौजूद है। इस बारे में बिजली मंत्री ने कहा कि बिजली वितरण कंपनी भारी घाटे में चल रही है, बावजूद इसके 2016-17 से बिजली शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। ऐबेका के प्रतिनिधियों ने इस बात का कड़ा विरोध किया और आंकड़े पेश करते हुए दिखाया कि घूमा-फिराकर उपभोक्ताओं पर बिजली के बिलों का बोझ कितना बढ़ा दिया गया है। अनगिनत खराब और बंद मीटरों का औसत बिल महीने दर महीने आ रहा है। इस बारे में वितरक निदेशक ने कहा कि डिजिटल मीटर खरीदे जा रहे हैं। इसलिए यह समस्या जल्द ही हल हो जायेगी।

ऐबेका की अगुवाई में विभिन्न स्तरों पर राज्यभर में चल रहे बिजली उपभोक्ता आन्दोलन के चलते राज्य के बिजली मंत्री को ये वादे करने पड़े हैं। यह आन्दोलन की जीत है। लेकिन ये वादे पूरे करवाने के लिए बिजली उपभोक्ता आन्दोलन का दबाव और बढ़ाने की जरूरत है। सुब्रत बिस्वास ने कहा कि 2021 में बिजली मंत्री ने ऐबेका के प्रतिनिधिमंडल से कहा था कि राज्य में स्मार्ट मीटर नहीं लगाये जायेंगे। लेकिन बाद में पता चला कि स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। इसके खिलाफ ऐबेका के बैनर तले पूरे राज्य में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा कड़ा विरोध किया गया। इसी के दबाव से 9 जून, 2025 को बिजली मंत्री को विधानसभा में कहना पड़ा था, 'स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे'। राज्य बिजली वितरण कंपनी और राज्य बिजली नियामक आयोग द्वारा बिजली मंत्री के कार्यालय को बार-बार यह बताने के बावजूद कि न्यूनतम प्रभार में वृद्धि से लघु उद्योग बंद हो जायेंगे, बिजली मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को 2023 में बताया था कि विश्व बैंक के प्रबल दबाव की वजह से न तो न्यूनतम प्रभार वापस लिया जा सकता है और न ही उसे घटाया जा सकता है।

अब, आसन्न विधानसभा चुनावों से पहले, वे उपभोक्ता संगठन के नेताओं से लघु उद्योगों को बचाने के जो वायदे कर रहे हैं, अगर उन्हें अमली जामा पहनाना है, तो लघु उद्योगों सहित हर श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं के संगठित आन्दोलन को तेज करने की जरूरत है।

PRGI Regn. No. 43022

श्रीलंका में फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में कॉमरेड शिवदास घोष की सीखों ने डाला जबरदस्त प्रभाव

'वर्ग को मजबूत करने के लिए वर्ग को मजबूत करो' के आह्वान पर श्रीलंका में मार्क्सवादी पार्टी फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी (एफएलएसपी) के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन में एसयूसीआई (सी) के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया।

1 मार्च को कोलंबो के सुगतदासा इंडोर स्टेडियम में आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में, जो श्रीलंका के वामपंथी छात्र-युवा कार्यकर्ताओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एक सुसज्जित विरोध प्रदर्शन के बाद हुआ, फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव कॉमरेड कुमार गुणरत्न ने अपने भाषण की शुरुआत की। उन्होंने देश-विदेश के आमंत्रित वामपंथी प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने भाषण में क्रांतिकारी जन आंदोलन गठित करने के लिए जनता की आवश्यक राजनीतिक शक्ति पैदा करने के लिए जन परिषद के गठन का आह्वान किया। उन्होंने 'क्रांतिकारी पार्टी में पेशेवर क्रांतिकारियों की जरूरत और पार्टी के नेता-कार्यकर्ता -समर्थकों के सर्वहारा संस्कृति अपनाने के अनिवार्य संघर्ष को याद किया।' उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में विश्व साम्राज्यवाद-पूंजीवाद सभ्यता को अभूतपूर्व संकट की ओर धकेल रहा है। हमारे देश में भी आपके देश की तरह हमारी पार्टी को भारतीय साम्राज्यवाद-पूंजीवाद के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है।

महान मार्क्सवादी विचारक कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं को याद करते हुए कॉमरेड सुभाष दासगुप्ता ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में वास्तविक वामपंथी और कम्युनिस्ट पार्टियों पर भारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए कम्युनिस्ट चरित्र, कम्युनिस्ट संस्कृति और कम्युनिस्ट जीवन शैली के आधार पर तीव्र

वैचारिक संघर्ष के जरिये क्रांतिकारी पार्टी की संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाना अब समय की मांग है। सही क्रांतिकारी पार्टी के नेता- कार्यकर्ताओं का संघर्ष सही सर्वहारा सांस्कृतिक मूल्यों को हासिल करने के संघर्ष से अलग-थलग नहीं रह सकता।

5 हजार से अधिक लोगों की मौजूदगी में कॉमरेड दासगुप्ता ने महान नेता कॉमरेड शिवदास घोष की इस अमूल्य शिक्षा को पेश किया कि 'केवल क्रांति चाहना ही कोई क्रांतिकारी चेतना नहीं है, बल्कि सही क्रांतिकारी चेतना है सही सर्वहारा वर्ग चेतना और सही सर्वहारा वर्ग चेतना है सही सर्वहारा वर्गीय पार्टी चेतना'-पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। सब लोग ध्यानमग्न होकर पूरी दिलचस्पी के साथ एसयूसीआई (सी) पार्टी के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके मनोवांछित बयान को वे कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं से प्राप्त कर रहे थे। भाषण के अंत में पार्टी की ओर से फ्रंटलाइन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव और श्रीलंका के प्रसिद्ध वामपंथी नेता कॉमरेड कुमार गुणरत्न के हाथों में महान लाल झण्डा और कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर और उद्धरण के साथ एक स्मृति चिन्ह बिरादराना रिश्ते के प्रतीक के रूप में पेश किया गया। जब कॉमरेड कुमार गुणरत्न ने एक हाथ में कॉमरेड शिवदास घोष की तस्वीर और उद्धरण अंकित स्मृति चिन्ह और दूसरे हाथ में कॉमरेड सुभाष दासगुप्ता के साथ लाल झण्डा थामा, तो पूरे स्टेडियम ने भारी जज्बे और जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया।

3 और 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एसयूसीआई (सी) के वक्तव्य ने उपस्थित प्रतिनिधियों के बीच जबरदस्त आकर्षण पैदा किया। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और यूरोप तथा लैटिन अमेरिका की विभिन्न वामपंथी पार्टियों और संगठनों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए और अपने विचार व्यक्त किये। जर्मनी की एमएलपीडी, तुर्की की एमएलकेपी, बांग्लादेश की बासद (मार्क्सवादी), अर्जेंटीना की रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, इटली की लोट्टा कम्युनिस्टा और श्रीलंका की न्यू डेमोक्रेटिक मार्क्सवादी-लेनिनवादी पार्टी। बासद (मार्क्सवादी) की केंद्रीय कमेटी के नेता कॉमरेड जयदीप भट्टाचार्य की बातों ने श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव डाला, खासकर जब उन्होंने कहा कि कॉमरेड शिवदास घोष की शिक्षाओं ने उनकी पार्टी के गठन में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है।

दक्षिण एशिया में वामपंथी राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण यह सम्मेलन सिंहली, तमिल और अंग्रेजी में गाये 'इंटरनेशनल' गीतों के साथ समाप्त हुआ।

ईरान पर संयुक्त हमले के खिलाफ ईरान-इजराइल-अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टियों का संयुक्त बयान

ईरान-इजरायल-अमेरिका की कम्युनिस्ट पार्टियों ने 6 मार्च को जारी एक संयुक्त बयान में ईरान पर अमेरिकी-इजरायली हमले का कड़ा विरोध किया और कहा कि यह युद्ध पूरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में और ज्यादा तबाही लायेगा। इस युद्ध का एकमात्र उद्देश्य साम्राज्यवादी हित साधने के लिए इस क्षेत्र और पूरे विश्व पर प्रभुत्व कायम करना था। इसका किसी भी देश के लोगों के किसी भी तबके की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। ईरान और लैटिन अमेरिका में भी ट्रम्प प्रशासन की 'हुकूमत बदलने' की महत्वाकांक्षा लोगों की स्वतंत्रता व गरिमा को तार-तार कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय कायदे-कानून, नियम व रीति-नीति का आज कोई मायने नहीं रह गया है।

फिलिस्तीन, इराक, लीबिया, सूडान, लेबनान सहित इस क्षेत्र के लगभग सभी देश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के शिकार हैं। प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासकों से जनता की मुक्ति न तो वाशिंगटन दिलायेगा और न ही तेल अवीव। यह मुक्ति केवल देश के लोगों के संघर्ष के जरिये, देशभक्तिपूर्ण नेतृत्व के संचालन के जरिये मिल सकती है।

इजराइल-अमेरिका आज इस क्षेत्र के सभी देशों पर अपने कब्जे के इरादे को सार्वजनिक रूप से घोषित कर रहे हैं। वे ईरान के लोगों को तानाशाहों और एकाधिकारी पूंजीपतियों से मुक्त कराने के लिए युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि ताकतवर क्षेत्रीय ताकत के रूप में ईरान के अस्तित्व को मिटाने और वहां अपनी कठपुतली सरकार कायम करने के लिए युद्ध कर रहे हैं।

इन तीनों समूहों ने, जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद के सिद्धांतों पर आधारित हैं, सभी देशों के स्वतंत्र और शांतिप्रिय लोगों से आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर आगे आयें और सभी अपने-अपने देशों की सरकारों पर दबाव डालें कि वे इस संकट के समय में युद्ध और आक्रमण के खिलाफ खड़े हों।

अरावली बचाओ कन्वेंशन आयोजित

रेवाड़ी : कन्वेंशन को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड राजेन्द्र सिंह

रेवाड़ी, हरियाणा।

28 फरवरी को यहां अरावली बचाओ आंदोलन, रेवाड़ी के तत्वावधान में अरावली बचाओ कन्वेंशन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व न्यायाधीश, पर्यावरण बोर्ड के सदस्य, शिक्षाविद, विभिन्न महकमों के पूर्व अधिकारी, सामाजिक संगठनों के सदस्यों, सोशल एक्टिविस्ट, एडवोकेट आदि गणमान्य व्यक्तियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की।

केन्द्र सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ दिल्ली में मजदूर-किसान संसद आयोजित

नई दिल्ली : केन्द्र सरकार की कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच द्वारा 9 मार्च को दिल्ली में जंतर-मंतर पर मजदूर-किसान संसद आयोजित की गई। इसमें भारत-अमेरिका व्यापार समझौते एवं अन्य अहम मुद्दों के खिलाफ जीत तक देशव्यापी संयुक्त संघर्ष का एलान किया गया। मजदूर-किसान संसद ने भारत सरकार से व्यापार समझौते पर भारत-अमेरिका अंतरिम रूपरेखा को अस्वीकार करने, विद्युत (संशोधन) विधेयक व बीज विधेयक 2025 को वापस लेने, वीबी ग्रामजी अधिनियम निरस्त करने और मनरेगा को बहाल करने तथा इसे 200 दिनों के कार्य और 700 रुपये दैनिक मजदूरी के साथ समृद्ध करने की मांग की।

मजदूर-किसान संसद ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि या तो कॉर्पोरेटपरस्त, अमेरिकापरस्त नीतियों व कानूनों को लागू करने के लिए जंगखोर व सत्तावादी उपायों को छोड़ दे या किसान-मजदूरों की सभी महत्वपूर्ण मांगों को पूरा करने और सभी जनविरोधी नीतियों को उलटने तक लगातार अखिल भारतीय एकजुट संघर्षों का सामना करे। संसद ने किसान-मजदूरों से बड़े पैमाने पर संघर्षों के लिए तैयार रहने का आह्वान किया और जनवाद-पसंद सभी मेहनतकशों से आंदोलनों का पूरा समर्थन करने की अपील की।

लगातार बड़े संघर्षों की तैयारी के हिस्से के तौर पर किसान-मजदूर मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ 23 मार्च को शहीद भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के शहादत दिवस को

दिल्ली : मजदूर-किसान संसद को संबोधित करते हुए एआईकेकेएमएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान

साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस के रूप में मनायेंगे, 4 श्रम संहिताएं लागू किये जाने के खिलाफ 1 अप्रैल को अखिल भारतीय काला दिवस मनाया जाएगा और कॉर्पोरेट-विरोधी जन संघर्षों को तेज करने के लिए सभी राज्यों में महापंचायतें आयोजित की जायेंगी।

सभी वक्ताओं ने असमान व शोषणकारी भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार ढांचे को स्वीकार करने और एक पर एक श्रमिक-विरोधी व किसान-विरोधी उपायों को लागू कर कॉर्पोरेट घरानों का स्वार्थ साधने के लिए अमेरिकी दबावों के आगे केंद्र सरकार के शर्मनाक आत्मसमर्पण किये जाने की कड़ी निंदा की।

एआईयूटीयूसी के कॉमरेड आरके शर्मा व एआईकेकेएमएस के कॉमरेड हंसराज राणा अध्यक्षमंडल में थे। एआईयूटीयूसी से कॉमरेड राजेन्द्र सिंह ने भी वक्ताओं में थे।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**